डाक पंजीयन सं. जयपुर सिटी/101/2020-22

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746

मीडिया दृष्टिकोण

वर्ष : 10 > अंक : 23 > मूल्य: 10 रुपए >पृष्ठ : 08

हिलव्यू समाचार

साप्ताहिक समाचार पत्र

जयपुर, मंगलवार, 14 नवम्बर 2023 (विशेषांक)

website: www.hsnews.in

शुभ दीपावली

सभी सुधि पाठकों को दिपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ।

नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा की काली कारगुज़ारियों का विस्तार से ख़ुलासा

राजकुमार शर्मा (माफ़िया माइंड)
(मुख्यमंत्री सलाहकार एवं नवलगढ़ विधायक आचार संहिता से पूर्व)

शातिर और क्रिमिनल माइंड का नाम है राजकुमार शर्मा

राजकुमार शिष्य बनकर बना अपने ही शिक्षक आचार्य द्विजेश का हत्यारा। छात्र जीवन से ही है पृष्ठभूमि में गुंडागर्दी व आपराधिक रिकॉर्ड

मासूम और भोले चेहरे के पीछे छुपा है आपराधिक दिमाग़

अशोक गहलोत का सलाहकार और राज़दार भी बना राजकुमार शर्मा

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर। जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) के संस्थापक आचार्य द्विजेश एकाकी जीवन जीने वाले युग पुरुष थे। जयपुर कॉलेज के अलावा अकूत व अथाह सम्पत्तियाँ उन्होंने अर्जित कीं थीं लेकिन उन्हें भोगने वाली गृहस्थी का सुख आचार्य के हिस्से नहीं आया।राजकुमार शर्मा एक शिष्य की तरह आचार्य से जुड़े और बेहद क़रीब रहकर यह राज़ भाँप ही लिया कि आचार्य द्विजेश का कोई वारिस नहीं। वर्तमान में नवलगढ़ विधायक रहे राजकुमार शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा के आपराधिक और शातिर दिमाग़ में उथल-पुथल मच गई फिर खेल शुरू हुआ संपत्ति को अपने कब्ज़े में लेने का। सेवा और सहयोग का सामंजस्य बैठाकर दिन रात आचार्य द्विजेश के इर्द-गिर्द राजकुमार शर्मा बना रहता और उसी वक़्त से कई ऐसे सबूत और गवाह अपने अनुसार इकठ्ठे करने शुरू किए जो वक़्त ज़रूरत पर सबूतों के तौर पर प्रस्तुत किये जा सकें। समय ने करवट बदली और आचार्य द्विजेश जी को उम्र और उसके साथ आने वाली बीमारियों ने आ घेरा। निरंतर बीमार रहने वाले आचार्य द्विजेश जो जीवन भर आत्मनिर्भर रहे वे राजकुमार शर्मा पर निर्भर हो गए या माहौल बनाकर निर्भर करवा लिए गए। लगभग 2017-18 के आसपास राजकुमार शर्मा ने आचार्य को जयपुर कॉलेज से अलग किया।

गांधी नगर M-16 के विधायक क्वार्टर में उन्हें रखा जहाँ 4-5 बाउंसर रखकर उन्हें नज़रबंद कर लिया गया इसके बाद उन्हें बापू नगर की हवेली SB-164 में रखा गया लेकिन किसी से मिलने के लिए बहुत सख्ती थी। ऐसा इंतजाम था कि उनके रिश्तेदार या कोई भी उनका सगा-सम्बन्धी उनसे न मिल सके और धीरे-धीरे उनकी करोड़ों की संपत्ति की जानकारी और उन पर अवैध कब्ज़ा करने की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी और एक दिन आचार्य की सम्पूर्ण संपत्ति का स्वयं को स्वयं ने ही सच का राजकुमार बना लिया यह इतना आसान नहीं था बाहरी ताक़तों का भी सहयोग ज़रूरी था इसीलिए सरकार में बैठे दिग्गज़ों को अपने खेमें में शामिल किया राजकुमार ने। नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बने और राज़दार भी यह प्रमाणित हुआ क्योंकि कई अवैध प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री पुत्र वैभव गहलोत भी पार्टनरशिप में मौजूद हैं। इसी के साथ स्वयं गहलोत और शांति धारीवाल ने इन्हें अपनी गैंग में शामिल कर लिया और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार का पद भी दिया ताकि जेडीए,नगर निगम, संपदा विभाग, रजिस्ट्रार कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड सभी विभागों से अवैध कब्ज़ों की फ़ाइलें बिना बाधा के आगे बढ़ सकें।

राजकुमार शर्मा न केवल धोखाधड़ी, जालसाजी मक्कारी,माफ़ियागिरी का नाम है बल्कि स्त्रियों की अस्मत के साथ खेलने वाला दरिंदा भी है जिसने कई औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। कुछ महिलाएँ इसके चँगुल से बच निकली और कुछ के चँगुल से यह स्वयं को न बचा सका जो आज इसकी पत्नी होने का दावा करती हैं और सेशन कोर्ट फैमिली कोर्ट में उनके साथ इसके मामले लंबित चल रहे हैं। अब तक सामने 3-4 महिलाएँ आ चुकी हैं जिसमें रूपा माथुर, निशा शर्मा (नवलगढ़), निशा शर्मा (जयपुर) और परमजीत कौर (पम्मा) के नाम मुख्य रूप से सामने आए हैं। लगभग 7-8 साल में आचार्य की करोड़ों अरबों की संपत्ति पर कब्ज़ा, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा,पुरानी हवेलियों पर कब्ज़ा कर हेरिटेज होटल बनाकर कब्ज़ा, जंगलातों की ज़मीनों पर कब्ज़ा,सूखे नालों,नदियों, लावारिस ज़मीनों पर कब्ज़ा करके राजकुमार शर्मा ने माफ़ियागिरी की हदें पार कर दीं लेकिन हज़ारों शिकायतों और परिवादों के बावजूद कार्यवाहियां ठंडे बस्ते में पड़ी रह गईं हैं वजह सबसे बड़ी यह कि कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शांति धारीवाल का साथ और आशीर्वाद इन्हें प्राप्त रहा है।

जयपुर कॉलेज की वह स्थिति जिसे किसी भी रूप में जीर्ण-शीर्ण नहीं कहा जा सकता लेकिन उसके बावजूद निगम पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दबाव बनाया कि पुनः मरम्मत का नोटिस जारी किया जाए ताकि पुनः मरम्मत की आड़ में राजकुमार शर्मा पुनः निर्माण का कार्य शुरू कर सके और हवामहल नगर निगम द्वारा औपचारिक नोटिस आचार्य द्विजेश के नाम जारी किया गया और पुनः मरम्मत की आड़ में परकोटे में अवैध पुनःनिर्माण शुरू कर दिया गया।

जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) चौड़ा रास्ता,जयपुर का अवैध नया स्वरूप जिसे काफ़ी विरोधों और हिलव्यू में लगातार प्रकाशित करने के बाद और यूनेस्को के दख़ल के बाद हैरीटेज लुक ही दिया गया लेकिन अवैध रूप से 5 मंज़िला फिर भी बनाया गया।

कार्यालय उपायुक्त हवामहल जोन(पश्चिम), नगर निगम जयपुर

नोटिस

अतः आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के तहत भवन मालिक/अधिभोगी/किरायेदारों को सूचित किया जाता है कि आप गिराऊ भाग को तुरन्त खाली कर गिरवा दें अथवा शेष भाग की मरम्मत करवाकर सुरक्षित स्थिति में कर लेवें।

हवामहल जोन (पश्चिम) नगर निगम जयपुर 18.9.2019 को जारी किया नोटिस जिसमें पुनः मरम्मत करवाने का आदेश दिया गया था इसके अतिरिक्त कोई स्वीकृति या आदेश पुनः निर्माण के लिए आज तक जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) के लिए नहीं दिया गया।

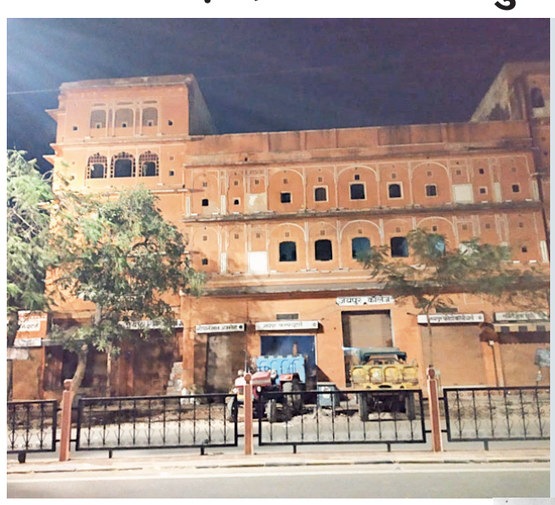

सूत्रानुसार ज्ञात है कि राजकुमार शर्मा ने दो वकील, दो सीए, एक अकाउंटेंट और कुछ ख़ास सहयोगी स्थायी रूप से नियुक्त कर रखे हैं जो इन सब षडयंत्रों और कारगुज़ारियों को न्यायिक दृष्टि से मज़बूत बनाते हैं। फ़र्ज़ी शपथपत्र, दस्तावेज़ और झूठे सबूत बनाते हैं। इस प्रकार राजकुमार शर्मा के साथ पूरी एक गैंग काम करती है। इसका ख़ुलासा जल्द होगा।

शिक्षक से विश्वासघात करने वाला शिष्य है राजकुमार शर्मा

भूखण्ड संख्या 697,जयपुर कॉलेज (नाना जी की हवेली) चौड़ा रास्ता जयपुर के संस्थापक आचार्य द्विजेश को कड़े पहरे में नज़रबंद क्यों कर रखा था राजकुमार शर्मा ने ?

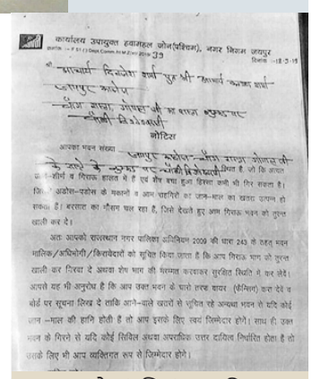

धीरे-धीरे जयपुर कॉलेज का मालिक बनने की कूटनीति रची राजकुमार शर्मा ने इस बीच बिना निगम स्वीकृति के निर्माण कार्य चलाया जयपुर कॉलेज का जिससे आचार्य सर्वथा अनभिज्ञ रहे और जैसे ही आचार्य द्विजेश शर्मा की मृत्यु 30 जनवरी 2023 को हुई राजकुमार ने स्वयं के पुत्र युवराज को आचार्य के शोक पत्र प्रकाशन में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि आचार्य द्विजेश की मृत्यु भी संदिग्ध तरीक़े से हुई और उनकी संपत्ति पर राजकुमार शर्मा का कब्ज़ा भी पूरी साजिश के तहत हुआ लेकिन अब तक यह मिस्ट्री पर्दे में है जो एक दिन ज़रूर उजागर होकर रहेगी।

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर गुरु दक्षिणा दी थी इसके ठीक विपरीत कलयुग के शिष्य राजकुमार शर्मा ने अपने शिक्षक आचार्य द्विजेश के विश्वास का गला काट कर,उनके पीठ में छुरा भोंक कर गुरु दक्षिणा दी है कि उनकी सारी संपत्ति पर अवैध रूप से जालसाजी कर कब्ज़ा कर लिया। उनका विश्वास जीतकर उन्हें उनके ख़ास रिश्तों और मिलने जुलने वालों से दूर कर नज़रबंद रखा जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अगर CBI या ED का छापा राजकुमार शर्मा के घर पड़ता है तो कई राज़ उजागर हो सकते हैं।

दिवंगत आचार्य द्विजेश शर्मा (संस्थापक जयपुर कॉलेज) जिनकी अकूत करोड़ों अरबों की चल-अचल संपत्ति पर राजकुमार शर्मा ने धोखाधड़ी और फ़रेब से कब्जा कर लिया है। यही नहीं कांग्रेस सरकार के सहयोग से जेडीए,नगर निगम में दबाव बनाकर,मिलीभगत करके सारी सम्पत्तियों को किसी न किसी रूप में अपने व अपने पुत्र के नाम से बनी ट्रस्ट के नाम कर लिया है। जेडीए में अक्सर राजकुमार शर्मा की गाड़ी खड़ी देखी जाती रही है।

मुख्य बिंदु

नाना जी की हवेली जयपुर कॉलेज को कभी पुनर्निमाण की अनुमति नहीं मिली उसके बावजूद 5 मंज़िला अवैध बिल्डिंग खड़ी कर दी गयी क्यों और कैसे?

हज़ारों विरोधों, शिकायतों,परिवादों और विवादों के बाद भी जयपुर कॉलेज नाना जी हवेली का अवैध निर्माण नहीं रुका और अवैध बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी जबकि परकोटे में नव निर्माण की कोई अनुमति नहीं मिल सकती थी क्यों?

किशनपोल जोन नगर निगम हेरीटेज से नाना जी की हवेली की फाइल्स हमेशा ग़ायब रहीं सूत्रों के अनुसार इसकी फाइल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बंगले में रहीं हमेशा क्यों?

राजकुमार शर्मा का अनिता कॉलोनी स्थित प्लॉट नं. A-20 पर अवैध कब्ज़ा कर अतिक्रमण और अवैध निर्माण

गाँधी नगर रेलवे स्टेशन

राजधानी के कई हिस्सों में अवैध कब्ज़ा कर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के न जाने कितने कच्चे चिट्ठे राजकुमार शर्मा की कारगुज़ारियों का हिस्सा हैं

A-20 अनिता कॉलोनी, गाँधीनगर, जयपुर पर अवैध कब्जे के साथ अवैध निर्माण।

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। राजकुमार शर्मा ने गाँधी नगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बजाजनगर मेन रोड़ पर अनिता कॉलोनी प्लॉट न.A-20 पर अवैध कब्ज़ा कर अवैध निर्माण ज़ोरों पर चला रखा है। गाँधी नगर रेलवे स्टेशन और बजाजनगर के बीच 100 फिट सड़क है जिस पर अवैध निर्माण ज़ोरों पर है और मालवीयनगर जोन नगर निगम ग्रेटर निष्क्रिय है और रेलवे विभाग की भी कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं है जबकि रेलवे स्टेशन के सामने मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनना अपने आप में बड़ा प्रश्न है। बिना निगम स्वीकृति के, नक़्शा, लेआउट, प्लान, भू-रूपांतरण लगातार अवैध निर्माण जारी है।

भारतीय वैवाहिक संस्कृति और न्यायिक प्रणाली की धज्जियाँ उड़ा रहा राजकुमार शर्मा

बिना तलाक़ के एक से ज़्यादा विवाह और तलाकशुदा पत्नी के साथ निरंतर निवास राजकुमार शर्मा के नैतिक,सामाजिक और चारित्रिक पतन को प्रमाणित करता है

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50
INDIA NON JUDICIAL
राजस्थान RAJASTHAN BL 503764

प्ररूप 26
(नियम 4 क देखिए)

नवलगढ़ (29) निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
राजस्थान विधान सभा (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ - पत्र

भाग - क

मैं... डॉ. राजकुमार शर्मा ... पुत्र/पुत्री/पत्नी ... श्री रामनिवास शर्मा... आयु ...50 वर्ष, जो ...ग्राम-पोस्ट - परसरामपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं (राज.) (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
NAWALGARH (Raj.) India

1/14

2

1. मैं ... इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस ... (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें)
2. मेरा नाम ... राजस्थान राज्य के नवलगढ़ (29) ... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या ...191... के क्रम संख्या ...193... पर प्रविष्ट है।
3. मेरा/मेरे ... 8890788907 ... सम्पर्क दूरभाष संख्या/संख्याए है/हैं और ... drrajkumaroffice781@gmail.com ... मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।
(i) ...https://www.facebook.com/Dr.RKSharmaOfficial...(facebook)...
(ii) ...dr.rksharmaofficial... (Instagram)...
(iii) ...Dr.RajkumarSharma... (twiter)...
4. स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय – कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैनएन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।		पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं डॉ. राजकुमार शर्मा	AXBPS2951C	2022-23	(i)	4,87,760/-
				(ii)	4,86,770/-
				(iii)	4,17,650/-
				(iv)	4,75,000/-
				(v)	3,00,000/-
2.	पति या पत्नी पूर्व पत्नी परमजीत से विवाह विच्छेद हो चुका है तत् पश्चात पत्नी निशा शर्मा विवाहिता है।	BINPS1118R	ज्ञात नहीं	(i)	ज्ञात नहीं
				(ii)	ज्ञात नहीं
				(iii)	ज्ञात नहीं
				(iv)	ज्ञात नहीं
				(v)	ज्ञात नहीं
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं	लागू नहीं	(i)	लागू नहीं
				(ii)	लागू नहीं
				(iii)	लागू नहीं
				(iv)	लागू नहीं
				(v)	लागू नहीं

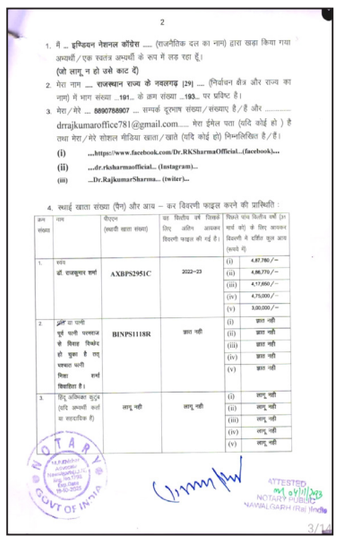

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
NAWALGARH (Raj.) India

3/14

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। 2023 विधानसभा के चुनाव नामांकन शपथ पत्र में राजकुमार शर्मा ने झूठे तथ्य पेश किए हैं। पत्नी परमजीत तलाकशुदा है तो साथ क्यों रह रही हैं? पत्नी रूपा माथुर और पत्नी निशा शर्मा जयपुर कौन हैं उनका राजकुमार शर्मा से क्या सम्बन्ध हैं। रूपा माथुर के पुत्र आदित्यराज शर्मा और निशा शर्मा की पुत्री विदुषी शर्मा के पिता फिर कौन हैं? ऐसे कई प्रश्न राजकुमार शर्मा के झूठे नामांकन ने खड़े कर दिए हैं। राजकुमार शर्मा भूमाफ़ियामेन ही नहीं बल्कि भारतीय सामाजिक संस्कृति का नाशक भी है। 3-4 शादियाँ बिना तलाक़ लिए करके उन स्त्रियों से संतानें उत्पन्न करके उन्हें लावारिस छोड़ देना इसकी प्रवृति में शामिल है।

रूपा माथुर, निशा शर्मा नवलगढ़, निशा शर्मा जयपुर, परमजीत कौर पम्मा की तरह कई स्त्रियों से प्रेम सम्बन्धों में राजकुमार शर्मा का नाम सामने आता रहा है। रूपा माथुर और निशा शर्मा जयपुर ने राजकुमार शर्मा के ख़िलाफ़ फैमेली कोर्ट और सेशन कोर्ट में परिवाद भी दर्ज कर रखे हैं जिनका अभी विवाद लंबित है। जगजाहिर चारित्रिक पतन के बाद भी राजकुमार शर्मा का नवलगढ़ विधायक बनना और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ख़ास होना कांग्रेस सरकार के चरित्र पतन को दर्शाता है।

हिलव्यू समाचार

राजापार्क

विशेषांक

जयपुर, मंगलवार, 14 नवम्बर 2023

नगर निगम ग्रेटर उपायुक्त स्वास्थ्य व अग्निशमन की रिपोर्ट से प्रमाणित)

पंचवटी सर्कल के आवासीय भूखण्डों में अवैध रूप से भभक रही भट्टियाँ

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। नगर निगम ग्रेटर की ग्रेट कार्यप्रणाली यह है कि वह ख़तरों को आमंत्रित करके चैन की नींद सो रहा है।

पूरा शहर भट्टियों में भभक रहा है लेकिन दोनों निगम हैरीटेज व ग्रेटर को कोई परवाह नहीं। आख़िर नगर निगम आरएमए लाइसेंस,फायर सेफ़्टी और फ़ूड लाइसेंस,शॉप लायसेंस की जाँच सख़्ती से क्यों नहीं करता। सीएमएचओ कार्यालय स्ट्रीट में बढ़ते फूड्स ठेले,वैनों व ढाबों,होटलों की जाँच क्यों नहीं करता?

क्या वजह है कि सबकुछ जानते बुझते हुए शासन-प्रशासन में बैठे अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस विषय को गम्भीरता से नहीं लेते और आये दिन हर रोज़ एक नया ठेला,ढाबा,थड़ी और होटल कुकुरमुत्ते की तरह उग जाते हैं।आख़िर क्या भ्रष्ट तंत्र की भ्रष्ट कार्यप्रणालियों और रीति-नीति ने ठान रखी है कि आमजन का सुख-चैन और सुरक्षा को पूरी तरह ख़त्म करके ही दम लेंगे!

चुनावी दौरों में किये गए वादों की पोटली नदी में फैंककर ये जनप्रतिनिधि पूरे पाँच साल अपनी जेब भरते हैं और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बन जाते हैं और जो नहीं बनते वो यायावर की तरह एक से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की सज़ा भोगते हैं।

आख़िर इन अवैध होटलों, ढाबों, ठेलों, निर्माणों, अतिक्रमणों को शैय तो भ्रष्ट तंत्र से ही मिलती है।

फ़ायर एनओसी,आरएमए लाइसेंस,फ़ूड लाइसेंस,कमर्शियल परमिशन,शॉप एक्ट और पार्किंग लाइसेंस नहीं है किसी के पास?

नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में सैकड़ों हादसों के बावजूद फायर सेफ़्टी, फ़ूड सेफ़्टी की कार्यवाहियाँ ठंडे बस्ते में क्यों हैं?

आवासीय में कमर्शियल अवैध निर्माण और कमर्शियल गतिविधियाँ पूरे शासनिक व प्रशासनिक सिस्टम को साबित करती हैं भ्रष्ट और बिका हुआ!

बन्नूवाल कमेटी की करोड़ों ज़मीन भूमाफ़ियाओं ने उठा रखी है लाखों के किराए पर। फ़र्ज़ी शपथपत्र (स्टाम्प) किराएनामे उड़ा रहे क़ानून की धज्जियाँ और साथ ही सैकड़ों भट्टियाँ बिना लाइसेंस जल रही हैं रोज़ाना। फ़ूड लाईसेंस और RMA लाइसेंस,फायर एनओसी नहीं है किसी के पास। CMHO विभाग और ग्रेटर निगम क्यूँ पालपोस रहा है माफ़ियाओं को यह जवाब देगा अब न्यायालय में। इस जगह पर लगभग 20 घण्टे भट्टियाँ भभकती हैं।

बन्नूवाल कमेटी के अंदर बाहर करोड़ों के किराए में संचालित हैं अवैध ढाबे। जहाँ लगभग 20 घण्टे भट्टियाँ भभकती हैं।

आवासीय प्लॉट न.211 रामगली न.02 भट्टी जलते हुए

- नगर निगम ग्रेटर के उपायुक्त स्वास्थ्य व अग्निशमन अधिकारी के पास नहीं है रिकॉर्ड कि बन्नूवाल कमेटी की पंचवटी सर्किल राजापार्क की जमीन पर चल रहे समस्त ढाबों व होटलों-सेठी रेस्टोरेंट एंड बार्बीक्यू, पूरण ढाबा, शर्मा अमृतसरी कुल्चा, अमृतसरी कुल्चा एवं भोजनालय वाला, द मोमोज़ हब व यू एंड मी,कुल्चा एंड कैफे प्रॉपर्टीज,मेडसुन फार्मेसी वह अन्य चल रही व्यवसाय गतिविधियों के प्रबंधक या मालिक द्वारा कब नगर निगम ग्रेटर या लोक प्राधिकरण में स्थाई व अस्थाई फायर एनओसी के लिए आवेदन किया गया है?
- यानी पंचवटी सर्कल बन्नूवाल कमेटी की ज़मीन पर संचालित ये ढाबे और होटल इन भूमाफियाओं के कब्जे की तरह फ़र्ज़ी और अवैध हैं
- ऐसे में अगर इस क्षेत्र में आगजनी या दुर्घटना हो जाये तो यहाँ ग्राहकों की कोई सुरक्षा नहीं है न ही कोई दुकानदार या ग्राहक क्लेम का हक़दार है।होटल ढाबों का स्टॉफ,ग्राहक इनकी जान-माल का कोई क्लेम नहीं? आवासीय भवनों में ढाबे, होटल, मिष्ठान की दुकानों का बढ़ता संचालन राजापार्क पँचवटी सर्कल के रहवासियों को एक बड़े खतरे की ओर ले जा रहा है।
- ढाबों होटलों में लगातार 15-20 घण्टे भट्टियों का भभकना और बढ़ता लोगों का घनत्व, लगातार बढ़ता जाम इस रिहायशी क्षेत्र सुख-शांति भंग कर रहा है।

पंचवटी सर्कल की इन सभी भट्टियों से भरे होटलों व ढ़ाबों के पास नहीं है फ़ूड लाइसेंस, आरएमए लाइसेंस,फ़ायर एनओसी और किसी भी तरह की सुरक्षा का सर्टिफिकेट

1. सेठी बारबिक्यु एंड ढाबा
2. पाली ढाबा
3. शर्मा अमृतसरी कुलचा
4. अमृतसरी कुल्चा एवं भोजनालय
5. यू एंड मी सोया चाप
6. पूरण ढाबा
7. अन्नू भाई एमबीबीएस
8. सोयाचाप एक्सप्रेस
9. मोमोज़ हब
10. अमृतसरी छोले कुलचे
11. सरदार जी बारबिक्यु
12. शंकर मिष्ठान भंडार
13. नंदलाल जी छोले
14. कुल्हड़ चाय वाला

हिलव्यू समाचार इस तरह की अवैध कमर्शियल गतिविधियों को लगातार प्रकाशित करता आ रहा है लेकिन शासन-प्रशासन की मिलीभगत व भ्रष्टाचार चरम पर है कि उसके कान में जूँ नहीं रेंगती मगर समय बड़ा बलवान है और उसके आगे बादशाह भी नतमस्तक हुए हैं। हिलव्यू समाचार तब तक लगातार प्रकाशन करता रहेगा इन अवैध धंधों और निर्माणों का जब तक कि शासन-प्रशासन कोई कार्यावाही नहीं कर देता।

सम्पादकीय

वैश्विक मंचों को उपयोगी व प्रभावी बनाने की ज़रूरत

विस चुनाव

डॉ. अश्वनी महाजन

विश्व में इस वक्त दो दो जंग जारी है, पश्चिम एशिया व खाड़ी क्षेत्र में भारी तनाव है, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद से लगातार मानवीय संकट है, पश्चिम व चीनी खेमे के बीच वर्चस्व को लेकर तनावपूर्ण स्थिति है, म्यांमार में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है, दो दर्जन से अधिक कट्टर इस्लामिक आतंकी गुट दहशतगर्दी कृत्य में लिप्त हैं, ईरान अमेरिकी प्रतिबंध का सामना कर रहा है, युद्ध व हिंसक संघर्ष के चलते खाद्य संकट गहराते जा रहे हैं व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो रही है, ऐसी विकट स्थिति में सबसे बड़े वैश्विक मंच संयुक्त राष्ट्र का सीमित भूमिका में रहना चिंतनीय है। भारत ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा उठाया है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र तंत्र, खासतौर पर सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के बोझ तले चरमरा रहे हैं। भारत ने रेखांकित किया कि महासभा को बहुपक्षवाद के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे का विस्तार करना चाहिए। भारत लगातार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाए जाने की मांग करता रहा है। भारत, जापान, जर्मनी व ब्राजील यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के प्रबल दावेदार हैं। यूएन सुरक्षा परिषद की स्थिति को देखते हुए ग्लोबल साउथ नया शक्ति केंद्र बनकर उभर रहा है। भारत शुक्रवार को 'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन भी कर रहा है। 'ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है, ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं। इस बैठक में विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों से उत्पन्न चुनौतियों और अधिक समावेशी विश्व व्यवस्था सुनिश्चित करने के तरीकों पर विमर्श होगा। यूएन के निष्प्रभावी होते जाने के चलते ही भारत विभिन्न ग्लोबल मंचों में अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है। वह क्वाड, आई2यू2, एससीओ, आसियान, दक्षेस, बिम्सटेक, ब्रिक्स, जी-20 आदि में सक्रिय है। भारत का प्रयास वैश्विक शक्ति संतुलन, वैश्विक शांति, समावेशी विकास और सभी मुल्कों की संप्रभुता का सम्मान व समंदर में मुक्त आवाजाही की रक्षा है और विस्तारवाद व संरक्षणवाद का विरोध है। भारत ने अमेरिका सहित आईपीईएफ के सदस्यों के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाने के समझौते पर किए हस्ताक्षर किया है। भारत व अमेरिका के अलावा आईपीईएफ समूह के 12 सदस्य और हैं। इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) समझौते से भारत जैसे सदस्य देशों की चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यह 'आईपीईएफ सप्लाई चेन रेजिलेंस एग्रीमेंट' अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा। आईपीईएफ का गठन पिछले साल 23 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। भारत वैश्विक संकटों के शांतिपूर्ण हल के प्रति सदैव चेष्टारत है। यूएन समेत सभी वैश्विक मंचों को उपयोगी व प्रभावी बनाना होगा।

> समय है, राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्रों के माध्यम से मतदाताओं को अपने दलों की नीतियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों से अवगत करवाने का। सभी राजनीतिक दल, मतदाताओं को अपने वादों से लुभाने का प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन पिछले डेढ़ दशक में चुनावी वादों का प्रकार बदला है। इन वादों में नीतिओं और कार्यक्रमों की बजाय नकद राशि हस्तांतरण और मुफ्त की स्कीमों की घोषणायें प्रभुखता से होने लगी हैं। महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों, अल्पसंख्यकों व अन्य कमजोर वर्गों को नकद हस्तांतरण, समस्त जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा समेत मुफ्तखोरी की घोषणाएं, अब एक आम बात हो गई है।

संकट का दूसरा नाम 'फ्रीबिज'

सात नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक देश के पांच महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव हमारे लोकतंत्र के उत्सव के रूप में जाने जाते हैं। आजादी के बाद चुनावों की सतत प्रक्रिया के चलते, भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उभरा है। यह समय है, राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्रों के माध्यम से मतदाताओं को अपने दलों की नीतियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों से अवगत करवाने का। इतिहास में सभी राजनीतिक दल, मतदाताओं को अपने वादों से लुभाने का प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन पिछले डेढ़ दशक में चुनावी वादों का प्रकार बदला है। इन वादों में नीतिओं और कार्यक्रमों की बजाय नकद राशि हस्तांतरण और मुफ्त की स्कीमों की घोषणाएं प्रभुखता से होने लगी हैं। महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों व अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को नकद हस्तांतरण, समस्त जनता को मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त यात्रा समेत कई मुफ्तखोरी की स्कीमों की घोषणाएं, अब एक आम बात हो गई है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के कर्ज माफ करने के अलावा, मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह, युवाओं को 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के अलावा, कई अन्य मुफ्त की स्कीमों की घोषणा की है। इसी प्रकार की घोषणाएं अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा की गई हैं। मतदाताओं को रिझाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में विचार करने का विषय है कि क्या यह हमारे लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। क्या हमारी सरकारें इन मुफ्त स्कीमों के लिए धन जुटा पाएंगी? कहीं राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा? इन मुफ्त की योजनाओं का सरकारी योजनाओं, सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च और उनके स्तर पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सभी प्रश्नों पर विचार करना जरूरी हो गया है।

दुनिया के कई देशों में मुफ्तखोरी के कारण सरकारी कर्ज के बढ़ने के उदाहरण मिलते हैं। वेनेजुएला और श्रीलंका इत्यादि के उदाहरणों से पता चलता है कि उन जैसे धनाढ्य देश भी मुफ्तखोरी की गलत आर्थिक नीतियों के चलते गरीब देशों से भी बदतर हालत में पहुंच सकते हैं, तो पाकिस्तान सरीखे विकासशील देशों की बिसात ही क्या है। वर्तमान में कल्याणकारी राज्य के नाम पर मुफ्त की स्कीमों के कारण कई अमीर देशों की भी एक लंबी सूची है, जो आज भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और अब वे इन स्कीमों को चलाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन यह बीमारी अब भारत के कई राज्यों में फैलती जा रही हैं। इस माह होने वाले चुनावों में तो राजनीतिक दलों ने मुफ्तखोरी की योजनाओं की घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। मुफ्त बिजली, मुफ्त यातायात, महिलाओं को अनुदान राशि, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, इत्यादि के साथ-साथ मुफ्त वाहन और कई अन्य मुफ्तखोरी की स्कीमों के बारे में हम रोज सुन रहे हैं। कुछ समय पहले भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के महालेखाकार एवं अंकेक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्टों में मुफ्तखोरी के कारण राज्यों पर बढ़ते कर्ज के बारे में आंकड़े प्रकाशित किए हैं और यह चिंता व्यक्त की है कि जहां-जहां मुफ्तखोरी की स्कीमें ज्यादा

चल रही हैं, उन राज्यों पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है।

गौरतलब है कि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार किसी भी राज्य में ऋण-जीएसडीपी (राज्य का सकल घरेलू उत्पाद) का लक्षित अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 'कैग' का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में यह अनुपात इस लक्षित अनुपात से कहीं ज्यादा है। पंजाब में यह 48.98 प्रतिशत, राजस्थान में 42.37 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 37.39 प्रतिशत, बिहार में 36.73 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 35.30 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 31.53 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.80 प्रतिशत, तमिलनाडु में 27.27 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 26.47 प्रतिशत तक पहुंच गया है और यदि राज्य के सरकारी उद्यमों और राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को भी शामिल कर लिया जाए तो 2020-21 तक राजस्थान में ऋण जीएसडीपी अनुपात 54.94 प्रतिशत और पंजाब में तो यह 58.21 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। आंध्र प्रदेश में भी यह 53.77 प्रतिशत आकलित किया गया है। इसके बाद तेलंगाना में यह 47.89 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 47.13 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी यह क्रमशः 40.35 प्रतिशत और 40.51 प्रतिशत है, और तमिलनाडु में यह 39.94 प्रतिशत। कैग का यह भी कहना है कि राज्यों का कर्ज लक्षित अनुपात की तुलना में लगातार बढ़ता जा रहा है। यह राज्यों के लिए ही नहीं, देश के लिए भी चिंता का विषय है। आंध्र प्रदेश के बारे में रिजर्व बैंक का कहना है कि पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करने वाला देश का दूसरा ऐसा राज्य है। गौरतलब है कि पंजाब में कुल कर राजस्व का 45.5 प्रतिशत मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होता है और आंध्र प्रदेश में 30.3 प्रतिशत। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर खर्च कर राजस्व का 28.8 प्रतिशत, झारखंड में यह 26.7 प्रतिशत है। गौरतलब है कि 'कैग' के आकलन के अनुसार उन राज्यों पर कर्ज ज्यादा है, जहां मुफ्त की स्कीमों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर पंजाब और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण का एक अन्य प्रांत तमिलनाडु है, जो जरूरत से ज्यादा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करता है। जब कोई प्रांत मुफ्त की स्कीमों पर अपने कर राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है तो स्वाभाविक रूप से आवश्यक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका पूंजीगत खर्च कम हो जाता है। किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि उसमें निवेश बढ़े। इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में निवेश प्रभावित होता है और उसके कारण राज्य का विकास भी। जरूरी है कि राज्यों द्वारा दी जा रही मुफ्त की स्कीमों पर अंकुश लगाकर विकास को गति दी जाए। जहां एक तरफ केन्द्र सरकार कोरोना काल में अपने ऋण जो सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के 61 प्रतिशत तक पहुंच गया था, को 56 प्रतिशत तक घटाने में सफल हो चुकी है, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारों के ऋण राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में संपूर्ण सरकार पर कर्ज बढ़ने के कारण देश की आर्थिक रेटिंग घटती जा रही है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो देश को निवेश मिलने में तो कठिनाई होगी ही, हमारी कंपनियों और सरकार के द्वारा जो विदेशों से ऋण लिया जाता है उस पर भी ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। यानी बढ़ते कर्ज न राजकोषीय असंतुलन पैदा कर रहे हैं, बल्कि राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं चलाने की क्षमता को भी प्रभावित कर रहे हैं और देश और उद्योग के विकास के लिए भी मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते देश को मुश्किल में न डाल सकें, इसके लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। राजनीतिक कारणों से विधायिका और सरकारी तंत्र शायद इस काम में सफल न हो सकें, लेकिन हमारे लोकतंत्र के अन्य स्तंभों जैसे न्यायपालिका और मीडिया को इसके लिए आगे आना होगा।

(लेखक दिल्ली विवि में प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

हिलव्यू समाचार

छबड़ा

विशेषांक

जयपुर, मंगलवार, 14 नवम्बर 2023

(छबड़ा-छिपाबड़ौद विधानसभा में हिलव्यू समाचार ने जानी जन-जन के मन की बात)

छबड़ा-छिपाबड़ौद की जनता किसको पहनाएगी विधायक का ताज़?

शालिनी श्रीवास्तव

छबड़ा/जयपुर (हिलव्यू समाचार)। कांग्रेस से करण सिंह राठौड़ और भाजपा से प्रताप सिंह सिंघवी एक बार फिर 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद आमने सामने हैं।

एक बार फिर वही मुक़ाबला जो आज से 15 साल पहले हुआ था करण सिंह राठौड़ ने प्रताप सिंह सिंघवी के प्रभुत्व को छबड़ा-छीपाबड़ौद से लगभग 6948 वोटों से जीत हासिल कर कम कर दिया।

हालांकि वो बदलाव का दौर था जनता बल्लू भैया यानी प्रताप सिंह सिंघवी को निःसन्देह जिताती आ रही थी लेकिन प्रताप के इर्द-गिर्द चिपके लोगों ने जनता और सिंघवी के बीच खाई खड़ी कर दी थी। प्रताप सिंह सिंघवी तक जनता की पहुँच को प्रभावित कर दिया और फिर जनता ने इसका जवाब चुनाव के दौरान प्रताप सिंह सिंघवी को नज़रंदाज़ करके दे दिया। उस दौरान करण सिंह राठौड़ की जगह कोई मरण सिंह कठोर भी होता तो अवश्य जीत जाता क्योंकि जनता में सत्ता के बदलाव की लहर और प्रताप सिंह सिंघवी को ग़लती का अहसास करवाने का भाव भरा हुआ था उनकी ही तरह उनको नज़रअंदाज़ करके। दूसरी और करण सिंह राठौड़ ने जिन कार्यकर्ताओं, साथियों और सहयोगियों के बल पर जीत हासिल की थी जीतते ही सब भूला दिया और सत्ता में चूर होकर पाँच साल गुज़ार दिये। जनता ने जो जवाब

प्रताप सिंह सिंघवी
छबड़ा-छीपाबड़ौद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी

करण सिंह राठौड़
छबड़ा-छीपाबड़ौद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी

बल्लू भैया को सबक के रूप में दिया था हराकर वही जवाब अगले चुनावों में करणसिंह को हराकर दे दिया।

एक बार फिर चुनावी मौसम ने अँगड़ाई ली है ऐसे में हिलव्यू समाचार ने छबड़ा में जनसंपर्क किया और जनता ने दिल खोल कर कही मन की बात।

आख़िर फिर एक बार आमने सामने होंगे प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह राठौड़!

2008 के विधानसभा का चुनाव परिणाम फिर से दोहराएगा समय या बिगड़ेगा सियासी समीकरण भाजपा का या कोई नया तीसरा चेहरा बनेगा विधायक?

निष्कर्ष

हिलव्यू समाचार ने जनता से बातचीत में अनुभव किया कि छबड़ा की जनता कांग्रेस और बीजेपी के दो पाटन में पीसने वाली प्राणी है क्योंकि तीसरे चेहरे पर विश्वास कैसे करे जब जाने-पहचाने चेहरों ने ही ठग रखा है क्योंकि-

- दोनों ही राजनैतिक पार्टी के विकास कार्य छबड़ा की आम जनता को याद नहीं।
- बिजली आज भी छबड़ा से घण्टों ग़ायब रहती है।
- सड़कें आज भी टूटी-फूटी हैं और सड़कों के इर्द-गिर्द आज भी अतिक्रमण क़ायम है।
- विधायक,पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के भूमाफ़ियायों और बिल्डर्स से गहरे सम्बन्ध हैं जो सरकारी और निजी भूमियों पर कब्जा करके दीमक की तरह देश को खा रहे हैं।
- प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान प्रताप सिंह सिंघवी के स्वायत्तशासन मंत्री बनने के बाद भी छबड़ा से कोटा का रास्ता आज भी उबड़खाबड़ और जानलेवा है।

छबड़ा के सभी लोगों की बाइट्स देखने के लिए www.hsnews.in पर विजिट करे।

- वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के होने के बावजूद करणसिंह राठौड़ जनता को राहत नहीं दिलवा सके इस समस्या से।
- दोनों पार्टी के नेताओं और माफ़ियाओं के बीच सरकारी ज़मीनों को लेकर बन्दरबाँट चलती रही है ।
- बिना अप्रूव्ड कॉलोनी में आम जनता के साथ भाजपा नेता काजू गेरा धोखाधड़ी करता है और विधायक प्रताप सिंह उसका संरक्षण करता है और उसके ख़िलाफ़ पुलिस को कार्यवाही से रोक देता है?

दिलीप यादव हनुवतखेड़ा के तालाब पर कब्जा करके हनुवतखेड़ा के लोगों और मवेशियों के पानी के ज़रिए को छीन लेता है और प्रताप सिंह सिंघवी उसमें उसका सहयोग करता है? काजू गेरा, दिलीप यादव जैसे भूमाफ़ियायों से साथ पार्टनरशिप में भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का नाम दबे-डरे शब्दों में जनता बयान करती है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती...क्यों?

यह नज़ारा छबड़ा से बाराँ के बीच की सड़कों का है जो लगातार कई सालों से है। सड़कें यहाँ सड़कें नहीं मौत का फ़रमान हैं ।

बजरंगनगर कॉलोनी, छबड़ा की अन अप्रूव्ड कॉलोनी है जिसमें भाजपा कार्यकर्ता काजू गेरा ने फ़र्ज़ी प्लॉट साइज़ काटकर फ़र्ज़ी नोटेरी बना कर प्लॉट बेचान कर दिए।

इस देहात में 360 गाँवों का विकास भाजपा ने किया है। वही आएगी। कांग्रेस के पार्षद तो 10-10 लाख में बिक गए क्योंकि 8 पार्षद भाजपा,16 पार्षद कांग्रेस, बाक़ी अन्य पार्षद थे फिर भी भाजपा का नगरपालिका अध्यक्ष बना।-**छबड़ावासी**

भाजपा को ही देंगे वही जीतेगी। उसी को वोट देते आये हैं। **छबड़ावासी**

कांग्रेस ने बहुत काम किया है। वही आनी है। ज़फ़र

कांग्रेस ही आएगी। जिन्होंने छबड़ा में दंगे किये चुनाव के बाद उनका भी ख़ुलासा होगा। किसने दंगे किये और करवाये सब सामने आएगा।-**शकील अहमद**

बीजेपी ही आएगी। विकास ही यह सरकार करवाती है।-**प्रवीण**

कांग्रेस ही आएगी। हमने हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिया है। छबड़ावासी

बीजेपी ही जीतेगी उसने काम बहुत किया है। -**छबड़ावासी**

हनुवतखेड़ा की जनता ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी की खोली पोल

दिलीप यादव हनुवतखेड़ा द्वारा छबड़ा के हाईवे 51 पर करोड़ों अरबों की ज़मीन को हड़पने का मामला हुआ उजागर

कुलदीप गुप्ता

छबड़ा (हिलव्यू समाचार)। हनुवतखेड़ा की जनता ने बताया कि दिलीप यादव नामक भूमाफ़िया लगातार हनुवतखेड़ा के तालाब को मिट्टी से (पाट) भर रहा है और दबाव प्रेशर बनाता है और धमकियाँ देकर कहता है कि इसमें विधायक प्रताप सिंह सिंघवी मेरे साथ पार्टनर हैं तुम्हारी कोई कार्यवाही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस और प्रशासन दोनों को खरीद रखा है मैंने।बाक़ी भाईसाहब यानी प्रताप सिंह सिंघवी सम्भाल लेंगे। इस तरह डरा-धमकाकर जनता की आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता रहा है।

मुख्य सड़क के किनारे पड़ी करोड़ों अरबों की ज़मीन को हथिया कर उस पर पेट्रोल पंप या होटल बनाने के सपने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और भूमाफ़िया दिलीप यादव दोनों देख रहे हैं। गाँव वालों के FIR करवाने जाने पर धमकियाँ देकर चुप रहने के लिए दबाव बनाया जाता है। **हनुवतखेड़ा की जनता की ज़ुबानी निकलकर आई पूरी कहानी-**

छबड़ा से मध्यप्रदेश हाईवे 51 पर हनुवतखेड़ा के 15 फीट गहरे तालाब से लगभग 8 गांवों के जानवर और प्राणी पानी पीते हैं और काम में लेते आ रहे हैं लेकिन माफ़ियामेन दिलीप यादव ने इस तालाब पर कब्जा कर लिया है।

हनुवतखेड़ा गाँव के लोगों से हिलव्यू टीम की सीधी बातचीत

हनुवतखेड़ा ग्रामवासियों के साथ कब्जा किये गए तालाब को देखने जाती हुई हिलव्यू समाचार की टीम

तालाब जिसे भूमाफ़िया दिलीप यादव ने कब्जा करके भर दिया है

छबड़ा शहर के बीच सड़ रही दवाई वाली बस्ती

दवाई वाली बस्ती के लोग जी रहे नारकीय जीवन

हिलव्यू समाचार छबड़ा बाराँ। लगभग 30-35 साल से भाजपा का वर्चस्व रहा है छबड़ा-छीपाबडौद विधानसभा में लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण योजना शौचालय अभियान की किरकिरी छबड़ा में देखी जा सकती है।

लगभग 20 साल पहले दवाई वालों को छबड़ा में कॉलेज के सामने बसाया गया। आवास कच्चे पक्के बनाकर दिए जिसमें तात्कालीन सरकार ने जमकर पैसा खाया। उसके बाद न सुध ली कॉलोनी की न ही कभी पानी की व्यवस्था पर ध्यान दिया। सार्वजनिक शौचालयों के हालात नरक से भी बदतर हैं न दरवाज़े हैं,न पानी हैं न ही मरम्मत हुई है कभी। इधर भाजपा विधायक प्रताप सिंह का कहना है "हमारा काम नहीं मरम्मत करवाना" नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश चन्द जैन भी बेसुध हैं ज़िम्मेदारी से। आख़िर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें जीते-जी नरक दिखा रही है जनता को और सारा सिस्टम अपने भ्रष्ट होने की कहानी चीख-चीख कर कह रहा है। एक बार दवाई वाली बस्ती के बीच जाकर देखें छबड़ा की सच्चाई कि पिछले 35 साल में क्या विकास हुआ है छबड़ा में ?

दवाई वाली बस्ती ने हिलव्यू समाचार को बताया कांग्रेस व बीजेपी दोनों सरकारों का सच !

बीजेपी कार्यकर्ताओं के दवाई वाली बस्ती में जनसम्पर्क के दौरान हिलव्यू समाचार ने उठाये बस्ती के नारकीय जीवन पर प्रश्न कि आख़िर सरकार ने क्या किया बस्ती के लिए जिसका संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए बीजेपी कार्यकर्ता।

इन सब क्यों का जवाब कौन देगा?

- 350 वोटर्स की बस्ती की किसी सरकार ने नहीं ली सुध आज तक क्यों?
- बीस साल पहले दिए गए आधे-अधूरे आवासों का सच इतना कड़वा है क्यों?
- दवाई वाला बस्ती में सार्वजनिक शौचालय टूटे फूटे, बिना दरवाज़े, सड़ा नाला सच्चाई बयान कर रहे कांग्रेस बीजेपी जैसी सरकारों की आख़िर इन सरकारों को फिर भी चाहिए इनसे वोट क्यों?
- काई और सड़ांध से भरे हुए नाले से फैल रही लगातार बीमारियाँ लेकिन होश में नहीं आयी है सरकारें आज तक क्यों?
- दवाई वाला बस्ती कर रही बहिष्कार मतदान करने का क्यों?

सरकार की आवास योजना में दिए गए मकानों की मरम्मत करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं:
-विधायक प्रताप सिंह सिंघवी

हनुवतखेड़ा का मामला मुझे पता नहीं अगर किसी के खाते की ज़मीन है तो उसका वो कुछ भी करे जनता का उसमें क्या दखल? मेरा दिलीप यादव से कोई सम्बन्ध नहीं।

प्रताप सिंह सिंघवी, विधायक
छबड़ा-छीपाबडौद विधानसभा

बिना दरवाजे के टूटे फूटे टायलेट।

कच्ची बस्ती के बीच सड़ता कीचड़।

उड़ता पंजाब बन रही आदर्शनगर विधानसभा

आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र पूर्णतया नशे की गिरफ़्त में

रफ़ीक ख़ान रहे पूरी तरह से नाकाम नशे को रोकने में युवा और बच्चे तक कर रहे हैं दिन और रात नशा

समाज सेवी कहलाने वाले रवि नैय्यर ने भी कभी कोई कोशिश नहीं की नशे की रोकथाम के लिए। जवाहर नगर कच्ची बस्ती के युवा नशे की लत और अपराध के दलदल में फँसते जा रहे लगातार।

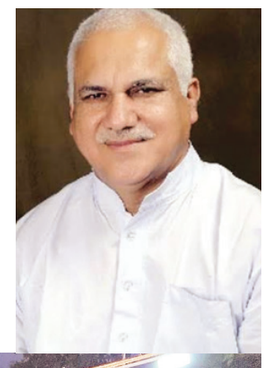

कुलदीप गुप्ता

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। हिलव्यू समाचार की ग्राउंड रिपोर्टिंग में आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र की काली सच्चाई आई सामने-

चुनावी रणभेरी बज चुकी है और मलाईदार विधानसभा क्षेत्रों में से एक आदर्शनगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने एक बार पुनः रफ़ीक खान को टिकिट दे दिया और वहीं बीजेपी ने अन्तिम समय में समाजसेवी नैय्यर को टिकिट थमाया है। बीजेपी ने अंतिम समय में टिकिट देकर अप्रत्यक्ष रूप से एक जुआ ही खेला है कि रवि नैय्यर आदर्शनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर सकें।

राजनीति का कोई विशेष ज्ञान नहीं । मात्र गो सेवक होने और गरीब लड़कियों की जनता के माध्यम से सहयोग लेकर शादी करवाने से ही जीत हासिल नहीं होती है। एक तरफ़ कुछ माह पूर्व ही आर्य समाज मन्दिर में हवन करने आये एक दम्पत्ति के साथ बदसलूकी करने बल्कि सरे राह महिला को जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी लग चुके है । एफ आई आर भी दर्ज़ हुई और आदर्श नगर थाने में अनुसंधान भी जारी रहा पर जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगे उपरोक्त प्रकरण में एफ आर लगवा दी गयी।वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से पूर्व विधायक रहे रफ़ीक ख़ान को टिकिट देकर मैदान में उतारा है पर इस बार रफ़ीक़ ख़ान के लिए भी सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रफ़ीक खान ने अपने पिछले कार्यकाल में सिर्फ़ अवैध निर्माणों से मोटी काली कमाई कमाने में अपना सारा समय गुजार दिया है। इस मोटी काली कमाई में वार्ड नम्बर 94 के बीजेपी पार्षद घनश्याम दास चन्दलानी ने भरपूर सहयोग दिया बल्कि वार्ड नम्बर 93 के कोंग्रेस के पार्षद नीरज अग्रवाल ने भी रफ़ीक खान का जमकर गुणगान किया पर जब रफ़ीक़ ख़ान ने नीरज अग्रवाल से दूरी बनाई तो फायदे का सौदा देख कर नीरज अग्रवाल अब रवि नैय्यर के साथ मैदान में आ कूदे हैं।

आदर्श नगर विधानसभा सभा क्षेत्र में आने वाले जवाहर नगर कच्ची बस्ती की दुर्दशा अपनी एक अलग ही कहानी कह रही है जिसमें एक खलनायक का किरदार निभाया है रफ़ीक खान ने।

छोटे छोटे बच्चे नशे के आदि हो चुके है जिसकी वजह से माँ बाप परेशान है।

लीजिये सुनते है जनता की ज़ुबानी इस आदर्शनगर विधानसभा के कच्ची बस्ती के क्षेत्र की कहानी

आदर्श नगर का क्षेत्र नशे का गढ़ बन चुका विशेष तौर से कच्ची बस्ती का पूरा इलाका नशे का घर बना हुआ है। पहले विधायक रह चुके रफ़ीक खान ने कुछ भी नहीं किया। कई बार पत्र लिखे, जाकर मिले पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई आज तक। - **महेन्द्र सिंह चौहान**

क्षेत्र में बिजली की समस्या भी रहती है साथ ही बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। पार्किंग की भी समस्या है । सड़के छोटी हो गई है।-**पदमा**

कोई भी नेता कोई काम नहीं करता है । कोई भी हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। जीतने के बाद सब भूल जाते है कोंग्रेस के राज में नशे के आदि हो चुके है युवा। -**श्रवण गौतम**

रफ़ीक खान के कार्यकाल में बस व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है । पहले यहाँ से 5 नम्बर, 6 नम्बर 10 नम्बर बस जाती थी जिससे आवागमन बहुत सुविधाजनक था पर अब बहुत दिक्कत है। अशोक परनामी के समय कच्ची बस्ती में ऐसा पानी आता था जिसे शौचालय के भी काम में नहीं लिया जा सकता था पानी की स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था।बीजेपी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है आख़िर क्यों ?- **सिंधु**

इस एरिया में पानी की बहुत कमी है टैंकर डलवाने पड़ते है फ्लैट में प्रॉपर पानी कि सप्लाई नहीं होती है। साफ सफ़ाई की भी दिक्कत है।-**दल्लूमल**

मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से त्रस्त है यहाँ जनता और उस से भी बड़ी बात की आदर्शनगर विधानसभा की कच्ची बस्ती के अलावा भी हर 400 कदम की दूरी पर ठेके खुले हुए है। अफीम ,स्मैक एवं गंजा खुले आम बिक रहा है युवा नशे की गिरफ्त में होता जा रहा है। -**गणेश**

अफ़ीम, गाँजा , स्मैक बेचने वाले लोगों को फांसी दो ताकि कोई भी ऐसी हरकतें नहीं कर पाए और हमारे बच्चे नशे की लत से दूर रहें । माँ बाप कितने परेशान है इसका अंदाज़ा किसी भी नेता को नहीं है । -**ललिता**

राजापार्क में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है । चाय में कोई केमिकल या किसी प्रकार का नशा डालकर पिलाते हैं । इस वजह से बहुत दूर तक के लोग चाय पीने आते हैं जिस वजह से काफी न्यूसेंस फैलता जा रहा है। पुलिस वाले दुकानदारों से पैसा ले लेते है तो कोई कार्यवाही नहीं करते है। -**प्रदीप सेवानी**

हाथ में नशे की सुईया लगाई जा रही है न रफ़ीक खान ने ध्यान दिया और न कभी रवि नैय्यर ने ध्यान दिया। कहने को एक विधायक रहे तो दूसरे अपने आप को समाज सेवक कहते हैं। -**कमल**

हिलव्यू समाचार पहुँचा सियासी चर्चा लेकर कोटा की जनता के द्वार

कोटा उत्तर में होगी काँटे की टक्कर

शांति धारीवाल
कांग्रेस प्रत्याशी कोटा उत्तर

जनता ही जाने,जनता के मन की बात
कोटा उत्तर से कौन पहनेगा सत्ता का ताज़?

इंदिरा गाँधी सर्कल, गुमानपुरा कोटा का दृश्य जिसके बायीं ओर कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र है।

प्रह्लाद गुंजल
भाजपा प्रत्याशी कोटा उत्तर

हॉट सीट कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल और बीजेपी से प्रहलाद गुंजल हैं आमने सामने

शालिनी श्रीवास्तव

कोटा/ जयपुर (हिलव्यू समाचार)। कोटा को हैरिटेज सिटी बनाकर जहाँ एक ओर धारीवाल ने कोटा की जनता का दिल जीता वहीं दूसरी और भ्रष्टाचार में हज़ारों कांड करके शांति धारीवाल सुर्खियों में भी रहे हैं।

'कौन है हाईकमान?' कहकर ख़ुद को राजस्थान का राजा समझने वाले शांति धारीवाल टिकट के लिए चुनावी समय में उसी हाईकमान के सामने गिड़गिड़ाने जा पहुँचे। इधर प्रह्लाद गुंजल घर के लिए सड़क पर कब्ज़ा करने से एक बार फिर जनता की नज़र में आए। न्यायालय के आदेश से विधि सम्मत कार्यवाही के आदेशों ने एक बार फिर जनता में न्यायालय की छवि और ताक़त को दुरुस्त किया।

कोटा में धारीवाल की डूबती नैया को थोड़ा सहारा मिला कि उन्हें एक बार फिर पार्टी से टिकट मिल गया और इधर प्रहलाद गुंजल भी टिकट लाने में क़ामयाब हो गए ओम बिरला के घर के चक्कर लगा लगा कर।

अब जनता ही जाने जनता के मन की बात कि उत्तर से कौन पहनेगा सत्ता का ताज़।

आइये जानते हैं कोटा की जनता से सत्ता के समीकरण को-

हाड़ौती बीजेपी का गढ़ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँगी बीजेपी की।
सड़क, सर्कल तोड़ना फिर बना देना कोई विकास नहीं। 150 से ऊपर सीटें भाजपा की होंगी। रोज़गार,मूलभूत सुविधाओं,आदि को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिवर फ्रंट की आवश्यकता क्या थी? रावतभाटा के पूरे गेट खोल दें तो रिवर फ्रंट के पत्थर धारीवाल के घर के पीछे ही मिलेंगे। एयरपोर्ट बनाते ताकि कोटा को नई सौगात मिलती।

तरुण गुप्ता का कहना है कि इस बार की राजनीति में कन्फ्यूजन है काँटें की टक्कर रहेगी लेकिन आएँगे धारीवाल ही

कोटा चमन हो गया।बहुत विकास हुआ है। कोचिंग सिटी बना है कोटा। धारीवाल जी के हारने की कोई वजह नहीं।

भाजपा ही आएगी हालांकि शांति धारीवाल ने भी बहुत काम किया है लेकिन इस बार बीजेपी की लहर ज़्यादा है। -मधु यादव

धारीवाल ने अच्छा काम किया है। रिवर फ्रंट जैसे आकर्षण पर्यटन के दूरगामी परिणाम अवश्य देगा। -रामेश्वर सुवालका

बलात्कार की एक ही सज़ा एनकाउंटर और मीडिया, ब्यरोक्रेसी,डेमोक्रेसी सबको सख़्त होना होगा। ***-दुष्यंत सिंह गहलोत***

समाज में परिवर्तन लाने की ताक़त रखती है मीडिया। मीडिया सबसे बड़ा आधार है लेकिन अब सकारात्मक ख़बरें आती ही नहीं!अख़बार और चैनल की ख़बरें छपने से पहले ही बिक जाती हैं।
-साजिद ख़ान

पर्यटन और मनोरंजन के हिसाब से कोटा में बहुत काम हुआ है। कौन जीतेगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।
-उषा मित्तल

धारीवाल ही आएंगे क्योंकि कोटा का बहुत विकास किया है धारीवाल ने।
-त्रिलोचन सिंह

मीडिया के लिए कोटा की जनता की सोच जो बहुत हद तक सच बयां करती है

आजकल मीडिया सच दिखाना भूल गया है

आम जनता ने कहा कि इसी डिजिटल दौर में मीडिया सच दिखाने में पिछड़ गयी है।नेता,अधिकारी अब तक बिकते थे लेकिन मीडिया में भी अब सब बिकने लगे हैं। सरकारें खरीद रही हैं मीडिया को। जनता के सामने नहीं आ रहा सच बाहर!

हिलव्यू समाचार

कोटा/जयपुर। आम जनता ने कहा कि मीडिया की भूमिका जहाँ एक ओर दृढ़ और सशक्त होनी चाहिए वहाँ दूसरी ओर मीडिया सच छुपाने लगी है बल्कि झूठ को सच बनाना भी मीडिया का काम हो गया है।

डिजिटल के इस दौर में मीडिया को तो और मज़बूत बनना चाहिए। आज हर आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है,कैमरा है ऐसे में सच बाहर आ ही जाता है जो मीडिया की बात को काटने की ताकत रखता है।

संविधान का चौथा स्तम्भ आज भी सबसे ताक़तवर है लेकिन अब मीडिया दुकानदारी करना सीख गया है ऐसे में नैतिक कर्तव्य ख़त्म होने लगे हैं। जनता का विश्वास डगमगाया है।

मीडिया चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन की दुकान ज़्यादा प्रतीत होता है ऐसे में वास्तविकता और सच्चाई प्रकाशित ही नहीं होती जो कि आम जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी है।

महिला सुरक्षा और रेप केस पर कोटा की जनता की राय

बलात्कारियों का हो एनकाउंटर... फाँसी हो उनको

शालिनी श्रीवास्तव

कोटा/जयपुर हिलव्यू समाचार। महिला सुरक्षा की चर्चा को लेकर जनता ने की खुलकर बात।

फाँसी हो या एनकाउंटर हो ऐसे लोगों का जो माँ, बहन,बेटी की इज्ज़त नहीं कर सकते हों। हालांकि जनसंपर्क था चुनावी चर्चा का लेकिन अब तक सबसे बड़े मुद्दे पर किसी भी सरकार ने गंभीरता से नहीं सोचा है ऐसे में हिलव्यू समाचार लगातार बलात्कारी और बलात्कार के विषय को गम्भीरता से उठा रहा है।

ऐसे में जनता के जागरूक लोगों ने सख़्ती के साथ बलात्कार और महिला उत्पीड़न पर बातचीत की और एक ही उपाय अधिकतर निकल कर आया कि बलात्कारियों को मौत की सज़ा ही हो जिससे सख़्ती बढ़ेगी और एक भय का माहौल बनेगा अपराधियों में।

महिला सुरक्षा क़ानून सख़्ती से लागू हो और ऑन स्पॉट हो शूट आउट ऐसे अपराधियों का

हिलव्यू समाचार

झालावाड़

विशेषांक

जयपुर, मंगलवार, 14 नवम्बर 2023

झालरापाटन-झालावाड़ में हिलव्यू समाचार ने जाना दो दशकों से वसुंधरा राजे सिंधिया के जमे रहने का राज़

2003 में सीएम, 2013 में सीएम और अब 2023
क्या यह 3 का आंकड़ा फिर होगा वसुंधरा के मुख्य राजतिलक का साक्षी?

वसुंधरा सा ही विशाल व्यक्तित्व है वसुंधरा राजे सिंधिया का

शालिनी श्रीवास्तव
झालावाड़/जयपुर (हिलव्यू समाचार)। लगातार जनसम्पर्क से महसूस हुआ कि आम जनता के दिलों पर राज करती आ रही है राजे। दो दशकों में 2003 और 2013 की तरह इस बार भी अंतिम अंक 3 ही है क्या 2023 भी होगा वसुंधरा राजे की झोली में वे हज़ार विरोधों के बाद भी एक बार फिर बन जायेंगी मुख्यमंत्री?

1984 से अपना राजनैतिक सफ़र शुरू करने वाली वसुंधरा सांसद भी रहीं और कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को राजनिति में मात देने वाली यौद्धा भी।

केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेन्द्र सिंह, सचिन पायलेट की माता जी रमा पायलेट, मिनाक्षी चन्द्रावत को हराकर अपनी ऐतिहासिक पहचान की तरह झालावाड़ की महारानी बन बैठी हैं। जड़ें इतनी मज़बूत रखीं हैं कि सालों साल और कोई उन्हें उखाड़ नहीं पायेगा।

देश-प्रदेश स्तर की बात करें तो वसुंधरा की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए केंद्र भी थोड़ा डगमगाया है लेकिन 2023 के चुनावी वर्ष ने वसुंधरा की ताक़त का अंदाज़ा केंद्र को अच्छी तरह करवा दिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया को नज़रंदाज़ करके प्रदेश में भाजपा मज़बूत छवि नहीं बना सकती। वसुंधरा सचिन पायलेट नहीं सुनामी है जो अपने साथ भाजपा के अस्तित्व को भी बहाकर ले जाने की ताक़त रखती हैं।

केंद्र से टिकट न मिलने से वसुंधरा के खेमे के विधायक भले कम हो जाएँ लेकिन अपने नाम में वसु यानी कुबेर धारण करने वाली और वसुंधरा की तरह धरती की विशालता धारण करने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया के व्यक्तित्व और शक्तित्व में अंश मात्र भी कमी नहीं आएगी।

आइये जनता ने जो कहा वो हम भी पढ़ते, समझते, और गुनते हैं-

बाराँ जिले की एक बार शक़्ल देख लें बस झालावाड़ के 20 साल पहले यही हालात थे लेकिन आज का झालावाड़ कोटा के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है वसुंधरा ने बल्कि कोटा की एयरपोर्ट सुविधा से कई गुना बेहतर है झालावाड़ की एयरपोर्ट फैसिलिटी।

झालावाड़ के मामा भांजा चौराहे पर से लाइव हिलव्यू समाचार।
झालावाड़ की जनता के अधिक व्यू जानने के लिए लॉग इन करें या सब्सक्राइब करें
hsnews यूट्यूब चैनल
वेबसाइट विजिट करें
गूगल क्रोम पर
www.hsnews.in

वसुंधरा मेडम का काम बहुत बढ़िया काम है उनको तो मुख्यमंत्री ही बनना चाहिए। सारी कौमों को साथ लेकर चलती हैं। ***-मोहम्मद आलम***

कांग्रेस आना चाहिए क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ग़रीबों की सरकार है। गढ़,अदालत,सड़क, सर्कल,साफ-सफाई सब वसुंधरा मेडम का बढ़िया काम है लेकिन ग़रीबों के लिए अनाज तो फ्री गहलोत ने बाँटें हैं। ***-उमराव***

- आम जनता से सीधी जुड़ती हैं वसुंधरा।
- 2003 का झालावाड़ और आज 2023 के झालावाड़ में रात दिन का फ़र्क़ जनता ही नहीं पर्यटक भी महसूस करते हैं।
- बड़े-बड़े अस्पताल, चौड़ी विशाल सड़कें, स्लीप लेंस,बड़े-बड़े चौराहे सर्कल,पार्क,मेडीकल कॉलेज, स्कूल, आर्ट कॉलेज,संस्थाएँ आदि।
- सफाई व्यवस्था ने झालावाड़ को नई पहचान दी है।
- अगर कोई शिक़ायत या परिवाद वसुंधरा तक लिखित या मौखिक पहुँचता है तो उस पर काम अवश्य होता है।

वसुंधरा का झालावाड़ में एकछत्र राज़ क्यों ?

- जनता ने बताया कि लिखित रूप में वसुंधरा कार्यालय से परिवादी या पीड़ित को उसकी समस्या के फॉलोअप मिलते हैं और समाधान के बाद फीडबैक भी माँगा जाता है संतुष्टि और असंतुष्टि का।
- 36 कौम को एक साथ एक जैसा व्यवहार देने में वसुंधरा का कोई सानी नहीं यह बात जनता के बीच जाकर पता लगी।
- मुस्लिम वर्ग का 80% वसुंधरा के साथ खड़ा दिखाई दिया।
- सीएम बनने के बाद भी वसुंधरा अपने क्षेत्र के लोगों के बीच हमेशा विधायक ही बनी रही हैं।
- आम जनता के बीच कभी भी कहीं भी पहुँच जाना वसुंधरा की पहचान है।

आम जनता का एकटुक जवाब:
किसी भी पार्टी का कोई भी दिग्गज़ से दिग्गज़ नेता वसुंधरा मेडम की टक्कर का नहीं!

महारानी साहिबा ही झालावाड़ के विकास की सबसे बड़ी वजह हैं उनके 20 साल के कार्यकाल ने झालावाड़ को 20 साल और आगे का विकास दिखाया है। ***-शंभू लोधा***

वसुंधरा मेडम ने न केवल विकास किया है झालावाड़ का बल्कि माहौल भी सुधारा है। महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा और सम्बल दोनों उनकी देन रहीं हैं। ***-आशा कासट***

राजे का कार्यकाल अच्छा रहा है। मिनी सचिवालय, रेलवे लाइन, हॉस्पिटल, पार्क, सड़कें सभी विकास किया है। सीएम उनको बनना ही चाहिए। ***-देवीलाल लोधा***

यूँ तो मेडम का काम बढ़िया है लेकिन अनाज मिलना बंद हो गया है । थोड़ा ग़रीबों की बिजली,पानी,अनाज भी कांग्रेस की तरह ध्यान देना चाहिए मेडम को! ***-राधा बाई***

विकास ही सबसे बड़ा कारण वसुन्धरा के झालावाड़ में जमे रहने की!
रिंकू चौहान

झालावाड में बहुत विकास किया है मेडम ने। कांग्रेस तो ख़त्म है यहाँ से! ***-शमशुद्दीन खान***

फूल में वोट देंगे उसी को देते आये हैं वोट
-माँगी बाई

कालीसिंध पुलिया बना दी,सड़कें, पार्क,सफाई सब तरफ़ विकास ही विकास दिखता है। 20 साल में झालावाड़ की सूरत बदल दी मेडम ने
दीपक वैष्णव

पब्लिक से संपर्क बनाकर रखती हैं। विकास तो बहुत हुआ है झालावाड़ में।
सग़ीर ख़ान

झालावाड़ की शक़्ल बदल दी मेडम ने। विकास बहुत ज़्यादा किया है।
नरेंद्र कुमार प्रजापत

दोनों सरकार अच्छा काम कर रही है। जिससे दिल राजी होगा उसी को वोट देंगे।
ममता बाई

सारी जातियों को उन्होंने बराबर तवज्जोह दी है। उन्होंने यहाँ से शुरुआत की है। बीजेपी जातिवाद का कार्ड खेल रही है लेकिन मेडम ने कभी जाति भेद नहीं किया इससे भी जनता का विश्वास उन पर बढ़ा है। ***-मोहम्मद सलमान***

अटरू-बाराँ विधानसभा में हिलव्यू समाचार.... जनता ने कही और हम सबने सुनी

बाराँ जिला कचरे से लथपथ आज भी पड़ा है खड्डे में

प्रमोद जैन भाया
अंता-बाराँ विधानसभा विधायक एवं खनन एवं गोपालन मंत्री राजस्थान (आचार संहिता से पूर्व)

पानाचंद मेघवाल
अटरू-बाराँ विधानसभा विधायक(आचार संहिता से पूर्व)

शालिनी श्रीवास्तव
बाराँ/जयपुर (हिलव्यू समाचार)। बाराँ जिले में प्रवेश करते ही वहाँ की राजनैतिक भ्रष्टता और प्रशासन की लचरता साफ नज़र आने लगती है।

आम जनता त्रस्त है किसी भी गली,क्षेत्र में चले जाएँ कचरा और गंदगी का ढेर बाराँ जिले के बदतर हालात बयां करते हैं। ऐसा लगता है कि पानाचंद मेघवाल और प्रमोद जैन भाया इस बाराँ जिले की पनौती हैं कि यहाँ का विकास रुका हुआ है।

जनता ने हिलव्यू समाचार से खुलकर बात की और बताया कि पानाचंद मेघवाल कांग्रेस नेता यहाँ का विधायक है लेकिन उसकी नहीं चलती वह भाया की कठपुतली है। सारा पावर भाया का चलता है ऐसे में यहाँ का विकास विनाश की ओर बढ़ रहा है।

हमने पाया कि जहाँ एक ओर वसुंधरा ने झालावाड़ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी वहीं दूसरी ओर भाया ने बाराँ जिले को विनाश की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

जनता में आक्रोश है लेकिन उसके बावजूद प्रमोद जैन भाया और पानाचंद क्यों जीत जाते हैं यह गम्भीर विषय है।

जनता का कहना है कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, संस्थाएं, मीडिया सबको भाया ने खरीद रखा है। दबदबा और भय इतना बना रखा है कि साँस भी लोग पूछकर लेते हैं ऐसे जागरूकता मर चुकी है और बाराँ की जनता ने खुलकर कभी इस तरह मन की बात नहीं कही लेकिन अब हिलव्यू समाचार के साथ जनता ने खोला है दिल और बयां की है सच्चाई बाराँ के हालातों की-

बाराँ में हर गली-मुहल्ले का यही हाल है

बाराँ के चार मूर्ति चौराहे पर बाराँ नागरिक सहकारी बैंक की गली के हालात। यह नज़ारा पूरे बाराँ में हर गली, मुहल्ले और यहाँ तक कि मुख्य सड़कों के किनारे किनारे भी देखा जा सकता है।

बाराँ की जनता ने सरेआम कहा कि पत्रकार, कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी सबको खरीद रखा है भाया ने

जाम पड़े नाले और कचरे में डूबी नालियाँ

बाराँ में लंबे समय से कीचड़ से भरे हुए नाले

कांग्रेस प्रत्याशी पानाचंद मेघवाल प्रमोद जैन भाया के इशारे पर ही काम करता है: रामपाल मेघवाल भाजपा नेता

अटरू भाजपा नेता रामपाल मेघवाल से हुई हिलव्यू समाचार संपादक शालिनी श्रीवास्तव एवं सह-संपादक कुलदीप गुप्ता की बातचीत के अंश

चर्चा में निकल कर आये कुछ ख़ास बिंदु, तथ्य और राज़-

- 2013 में भाजपा से विधायक रहा हूँ अटरू से: रामपाल मेघवाल
- प्रमोद जैन भाया का अटरू,किशनगंज के कांग्रेस विधायकों पर इस तरह कब्जा है कि वे इनके इशारे के बिना जनता को उपलब्ध भी नहीं रहते।
- पानाचंद मेघवाल और प्रमोद जैन भाया ने अटरू और बाराँ को बर्बाद कर दिया है विकास के नाम पर ज़ीरो हैं ये दोनों क्षेत्र!
- अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल पर ब्राह्मण हत्या के संगीन आरोप भी लगे हैं लेकिन पावर पोजिशन ने सब दबा दिया है।
- हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं हिन्दू, सिख,ईसाई या मुसलमान नहीं।
- सनातन धर्म को ख़त्म करने के चक्कर में कहीं कांग्रेस का ही ख़ात्मा न हो जाये।
- केंद्र सरकार का सारा पैसा ये कांग्रेस नेता लूट कर खा गए हैं इसीलिये विकास नहीं विनाश हुआ है।
- साढे तीन साल में सड़क का काम नहीं हुआ जब चुनाव आये तब काम शुरु करके विकास दिखा रहे हैं कांग्रेस नेता क्योंकि जनता सड़क की टूट फूट को लेकर ख़ासी नाराज़ है।

जनता के प्रश्नों में छुपी शिक़ायतें और दर्द

- बेरोज़गारी और गंदगी बाराँ जिले की पहचान बन चुके हैं?
- विकास के नाम पर कांग्रेस ने कचरे के ढेर दिए हैं बाराँ को?
- क्या पानाचंद मेघवाल जनता का नहीं प्रमोद जैन भाया का सेवक है?
- क्या प्रमोद जैन भाया को आम जनता की परेशानी से कोई मतलब नहीं?
- पूर्व बाराँ जिला कलेक्टर इंदर सिंह राव के रिश्वतखोरी कांड का हवाला देते हुए बाराँ की जनता ने खोले कई और राज़!
- क्यों कचरे के ढेर में पड़ा सड़ रहा बाराँ जिला आज भी?
- बिजली आज भी पूरी नहीं बाराँ में?
- गुंडागर्दी मचा रखी है प्रमोद जैन भाया ने बाराँ में कोई सुनवाई नहीं होती किसी की क्यों?
- कमल राठौड़ को फंसाया झूठे मुकदमों में क्योंकि कमल राठौड़ ने बाराँ जिले में करवाये थे विकास कार्य,क्यों?
- गौ शाला और सामूहिक विवाह सम्मेलन में बाहर की भीड़ होती है लोकल आम जनता नहीं हुई आज तक शामिल। भाया यह दिखावा करके जनता को ठगता है और दुनिया के सामने जनसेवक बनता है।
- बाराँ आज भी विकास के नाम पर ज़ीरो है क्यों?

विधायक तो पानाचंद मेघवाल है लेकिन भाया की चलती है यहाँ इसीलिए आज तक विकास नहीं हुआ।

100 रुपये सरकार से आते हैं और विकास में 25 भी नहीं लगते इसीलिए बाराँ गड्ढे में है।

भाया है बदमाश आदमी उसी ने बाराँ को बर्बाद कर रखा है

अटरू से बाराँ कोटा मार्ग के हालात कई सालों से ऐसे ही हैं। मरम्मत होती है लेकिन भ्रष्टाचार के कारण केवल दिखावा होता है बाक़ी सड़क पक्की दुरुस्त आज तक नहीं हुई।

कमल राठौड़ ने बाराँ में काम करवाया लेकिन अच्छे आदमी को जेल पहुँचा देते हैं भाया जैसे लोग।

कमल राठौड़ जिला परिषद प्रमुख ने बाराँ में बहुत विकास किया सर्कल,पार्क,सफाई सभी बढ़िया काम किये लेकिन प्रमोद जैन भाया को यह रास नहीं आया उसे जेल भिजवा दिया उसके पेट्रोल पम्प, घर,व्यापार को बर्बाद कर दिया।

बाराँ पूरा ज़ीरो है विकास के नाम पर कुछ नहीं। बाराँ में रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं है।

सब खावड़े हैं पैसा खाने राजनीति में आते हैं

बाराँ में पानी,कचरा,गंदगी,बेरोजगारी है। यह गाँव कहलाने लायक भी नहीं जिला तो दूर की बात है

नेताओं से पूछो कि क्या किया है उन्होंने यहाँ?

गारा में पड़ा है बाराँ। सरकार बदलनी चाहिए। नई सरकार आम आदमी बनाएं।

बाराँ कोई जिला जैसा नहीं यहाँ कोई विकास नहीं है

कमल राठौड़ ने बाराँ जिला को चमकाया है। नेताओं से कौन भिड़े?

कलेक्टर, क्लर्क, पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी सबको खरीद रखा है भाया ने इसीलिए सब चुप हैं और बाराँ बर्बाद है।

इसको आप जिला कैसे कह सकते हो। ओवर ब्रिज अधूरा पड़ा है। शहर गड्ढे से भरा पड़ा है। आम आदमी ही अब अपने लिए खड़ा हो तो कुछ हो सकता है।

हिलव्यू समाचार

घोटाला

विशेषांक

जयपुर, मंगलवार, 14 नवम्बर 2023

पूर्व आयुक्त महेंद्र सोनी और ओसवाल डाटा कम्पनी की मिलीभगत से करोड़ो का राजस्व नुक़सान ग्रेटर नगर निगम में आज तक जारी...

क्यों नगर निगम ग्रेटर में 20 करोड़ का नुक़सान देने वाली ओसवाल डाटा कंपनी आज भी दे रही सेवाएँ?

ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर के संज्ञान में सारा मामला है उसके बावजूद कोई कार्यवाही या जाँच अब तक क्यों नहीं हुई?

IAS महेंद्र सोनी और मैसर्स ओसवाल कम्प्यूटर्स एंड कंसल्टेंट के बीच 2.5 करोड़ का आंकड़ा क्या है?

नगर निगम ग्रेटर ओसवाल डाटा कंपनी के फ़र्ज़ीवाड़े के बावजूद उसे निकाल क्यों नहीं रहा क्यों? 2005 से महेंद्र सोनी की मेहरबानी से ओसवाल डाटा को मिला काम उसके बाद लगातार महेंद्र सोनी से लेन-देन कर करोड़ो की कंपनी बना ली ओसवाल ने। प्रमोटी आईएएस महेंद्र सोनी के पास लगातार पहुँच रही है मासिक बंदी।

ग्रेटर नगर निगम पूर्व आयुक्त महेंद्र सोनी इस राजस्व घोटाले के सूत्रधार हैं।
सूत्रों के अनुसार जो चुपचाप ओसवाल डाटा कंपनी से ढाई करोड़ की रक़म लेकर निगम से स्थानांतरित हो गए और ओसवाल डाटा कंपनी का उद्धार कर गए।

वर्तमान आयुक्त बाबूलाल गोयल ने अब तक ओसवाल कम्प्यूटर्स एंड कंसल्टेंट कंपनी के बड़े घोटाले के जाँच के आदेश क्यों नहीं दिए? हिलव्यू समाचार लगभग एक से डेढ़ माह पूर्व सारा मामला इनके संज्ञान में ला चुका है।

ओसवाल डाटा कंपनी की सेवाओं पर निरंतर खड़े रहे हैं कई सवाल

- 2005 से 2023 तक लगातार 18 साल कैसे एक ही कंपनी को टेंडर दे रही है नगर निगम ग्रेटर जबकि किसी भी कंपनी की सेवाएँ पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स (RTPP) के तहत किसी भी निजी कंपनी या फर्म का टेंडर सरकारी सेवाओं में 3 साल से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता अगर बढ़ाया जाता है तो सरकार का अनुमोदन लिया जाना अनिवार्य है।
- DOIT ने अब तक इस फ़र्ज़ीवाड़े पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की कि उसके संज्ञान में लाये बिना,उसकी अनुमति बिना किस तरह ओसवाल डाटा कंपनी की सेवाओं में विस्तार हुआ?
- 27 दिसम्बर 2022 को वित्तीय सलाहकार ग्रेटर नगर निगम ने ओसवाल डाटा कंपनी की सेवाओं में ख़ामियों पर आपत्ति दर्ज की जिसमें ओसवाला डाटा कंपनी द्वारा फेज़ 1 और फेज़ 2 का कार्य पूर्ण नहीं किया गया जबकि इस काम की राशि 82.40 लाख रुपये भुगतान की गई जो राजस्व का बड़ा नुक़सान था।
- इसी के साथ निगम की संपत्तियों का सर्वे अनुबंध शर्तानुसार संख्या 20 व 21 के तहत नहीं किया गया उसकी पेनल्टी भी नहीं वसूली गयी। डबल एंट्री सिस्टम को ओसवाल कंपनी ने फॉलो नहीं किया जिससे 19.20 लाख की राजस्व हानि हुई यह व्यर्थ का भुगतान कंपनी को किया गया।

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। 2005 में निजी फर्म मैसर्स ओसवाल कंप्यूटर्स एंड कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड की नगर निगम में एंट्री तत्कालीन उपायुक्त महेंद्र सोनी के कारण ही हुई थी जो वर्तमान में आयुक्त नगर निगम ग्रेटर के पद से रिलीव हुए लेकिन महेंद्र सोनी अपने पद और पावर का दुरूपयोग करके ग्रेटर निगम से जाते जाते हज़ारों शिकायतों से युक्त ओसवाल डाटा कंपनी को 20% दरों में वृद्धि भी दे ही गए और रिश्वत के करोड़ो समेट कर चले गए। सबसे बड़ी बात यह कि ओसवाल डाटा कंपनी जो लाखों के नुक़सान की दुहाई देकर महेंद्र सोनी से मिलीभगत करके और सोनी को भेंट चढ़ाकर अपनी सेवाओं में 20% वृद्धि करवा चुकी थी वही नुकसान में डूबी फ़र्ज़ी कंपनी महेंद्र सोनी के जाते ही बढ़ी दरें कम करके यानी दर वृद्धि का तनाव छोड़कर सेवाओं में वृद्धि की गुहार लगाने लगी क्योंकि पुनः एक बार कंपनी को हायर करने के टेंडर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी।

मैसर्स ओसवाल कंप्यूटर्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं नगर निगम ग्रेटर से कुछ प्रश्न-

- उपरोक्त फर्म का टेंडर वर्ष 2012 में समाप्त हो गया फिर किस आधार पर फर्म लगातार सेवाओं में सक्रिय रही?
- उपरोक्त फर्म द्वारा दिए गए कार्यों व सेवाओं की पूर्णता में कमी के बावजूद निगम ग्रेटर ने इसे बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया?
- उपरोक्त फर्म की राशि दर लगातार बढ़ाई गई जबकि उसकी सेवाओं में और उसके परिणामों में कमियां रही क्यों?
- प्रति कंप्यूटर औसत 17000 रुपए का भुगतान उसे दिया जा रहा है जो की अन्य राजकीय संस्थाओं से कई गुना ज्यादा है क्यों?
- इससे कम दर में अन्य फर्मे मेन विद मशीन की आपूर्ति कर रही है फिर यही डाटा कंपनी निगम में क्यों
- मैसर्स ओसवाल डाटा फर्म द्वारा टेंडर से संबंधित बैठक में उपस्थिति भी पूर्ण नहीं रही जबकि फर्म द्वारा उल्लेखित है कि ऑपरेटर का प्रतिमाह सत्यापन किया जाता है, कैसे?
- स्वीकृत ऑपरेटर की संख्या कम ऑपरेटर फर्म द्वारा दिये जा रहे हैं जो कि ओसवाल फर्म की ग़लत कार्यप्रणाली को प्रमाणित करता है।
- ऑपरेटर्स को स्वीकृत राशि से कम राशि प्रतिमाह दी जा रही है जो कि सरासर धोखाधड़ी है
- फर्म द्वारा उल्लेखित है कि नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के साथ जोन कार्यालय में मुरलीपुरा,विद्याधर नगर, झोटवाड़ा,मालवीय नगर,सांगानेर,मानसरोवर,जगतपुरा एवं डीएलबी,सचिवालय सहित सभी में मेन विद मशीन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जबकि इतने सारे कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की उपस्थिति किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है यह संदिग्ध मामला है।
- नगर निगम ग्रेटर में ओसवाल फर्म द्वारा उपभोग में ली गयी बिजली की ऑडिट विद्युत शाखा द्वारा 1 करोड़ के लगभग निकाली गई जिसे 20% दर और समयावधि बढ़ाते वक़्त व भुगतान करते वक़्त लगातार नज़रंदाज़ किया जाता रहा है और वसूली आज तक नहीं की गई हैं।?

क्या राज्य निर्वाचन आयोग की नहीं कोई हैसियत बीकानेर नगर निगम के सामने?

क्या बीकानेर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा के लिए आचार संहिता के नहीं हैं कोई मायने?

09 अक्टूबर 2023 को आचार संहिता लगने के बावजूद बीकानेर नगर निगम आयुक्त केसरलाल मीणा द्वारा धड़ाधड़ी से पट्टे बाँटें गए क्यों?

शालिनी श्रीवास्तव

बीकानेर/जयपुर (हिलव्यू समाचार)। 09 अक्टूबर 2023 से राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है किंतु नगर निगम बीकानेर में नियुक्त आयुक्त केसर लाल मीणा आचार संहिता का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं और आचार संहिता लागू होने के बाद भी वह रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बैक डेट में पट्टे जारी कर रहे हैं। यह राज्य निर्वाचन आयोग के गाल पर ज़ोरदार तमाचा है क्योंकि आचार संहिता की कोई हैसियत नहीं आयुक्त केसरलाल मीणा के सामने।

हिलव्यू समाचार ने भी राज्य निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लिखित परिवाद के रूप में मामला दर्ज किया है किंतु अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार के कई लोगों को पट्टे जारी किए हैं जो भ्रष्टाचार का पुख़्ता प्रमाण हैं। मोटी रक़म लेकर पट्टे का खेल खेल गए हैं आयुक्त केसर लाल मीणा। जिसमें उनके ड्राइवर विजय और सुनील सबसे बड़े सहयोगी हैं जो निगम में पूरा माहौल बनाकर रखते हैं और किसका काम कैसे होगा यह सूचना आयुक्त केसरलाल मीणा तक पहुँचाते है। लेन-देन का पूरा काम ड्राइवर सुनील ही सम्भालता है।

RAS केसरलाल मीणा, आयुक्त नगर निगम बीकानेर से वर्जन लेने हेतु कॉल किये गए लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाए। हिलव्यू समाचार की टीम जल्द बीकानेर जाकर ही उनका वर्जन लेगी।

फ़र्ज़ी तरीक़े से बैक डेट में जारी पट्टों की सूची इस प्रकार है जिस पर निर्वाचन आयोग को तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए-

1. भैरूलाल पुत्र योगराज सोनी
   डिस्पैच 703/09 अक्टूबर 2003
2. सुशील कुमार सुराणा पुत्र तोलाराम सुराणा
   डिस्पैच 706/09अक्टूबर 2023
3. मधु देवी सुराणा पत्नी मोहनलाल सुराणा
   डिस्पैच 708/09अक्टूबर 2023
4. मुकेश कुमार सोनी, भंवरलाल सोनी
   डिस्पैच 710/09अक्टूबर 2023
5. गंगा देवी पत्नी गौरी शंकर
   डिस्पैच 712/09अक्टूबर 2023
6. सुमन गोयल पत्नी अशोक गोयल
   डिस्पैच 714/09अक्टूबर 2023
7. रितेश गोयल पुत्र अशोक गोयल
   डिस्पैच 717/09अक्टूबर 2023
8. अशोक गोयल पुत्र बाबूलाल गौयल
   डिस्पैच 718/09 अक्टूबर 2023
9. दुर्गादास किराड़ पत्नी श्यामसुंदर एवं श्याम सुंदर पुत्र भागचंद किराड़
   डिस्पैच 720/09 अक्टूबर 2023
10. राजेन्द्र प्रसाद
    डिस्पैच 722/09 अक्टूबर 2023
11. कुसुम जैन पत्नी सुरेंद्र जैन
    डिस्पैच 724/09 अक्टूबर 2023
12. विजय कुमार पुत्र चाँद रतन हर्ष
    डिस्पैच 726/09 अक्टूबर 2023
13. कमला देवी पत्नी चाँद रतन हर्ष
    डिस्पैच 728/09 अक्टूबर 2023
14. गौरीशंकर शर्मा पुत्र रामर्दन शर्मा
    डिस्पैच 730/09 अक्टूबर 2023
15. मदन गोपाल खत्री पुत्र भंवरलाल खत्री
    डिस्पैच 732/09 अक्टूबर 2023
16. सरस्वती देवी पत्नी पूनमचंद चौधरी, विलास पुत्र पूनमचंद चौधरी, सुनीता चौधरी पत्नी विलास चौधरी
    डिस्पैच 734/09 अक्टूबर 2023

इस सम्बंध में बीकानेर नगर निगम के आयुक्त व ड्राइवर की टिप्पणी के लिए कॉल किये गए लेकिन...

- आयुक्त केसरलाल मीणा का कॉल रिसीव नहीं हुआ अतः वर्जन नहीं लिया जा सका।
- केसरलाल मीणा आयुक्त के ड्राइवर विजय ड्राइवर का कहना मैं सफाई कर्मचारी हूँ लेकिन निगम ने ड्राइवर लगा रखा है मेरा इस सम्बंध में कोई मतलब नहीं!
- आयुक्त केसरलाल मीणा के दूसरे ड्राइवर बबलू उर्फ़ सुनील ने कॉल अटेंड करके काट दिया।
- **सभी पट्टे आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बावजूद निरंतर बाँटें गए जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है और इसी के साथ कुछ ख़ास तथ्य हैं जो इस भ्रष्टाचार को प्रमाणित करते हैं-**
- बीकानेर नगर निगम की जिस शाखा इज़ाज़त तामीर से पट्टे डिस्पैच किए गए हैं उस शाखा में पट्टे जारी करने का कार्य नहीं होता।
- इसी के साथ-साथ इज़ाज़त तामीर शाखा की प्रभारी दिनाँक 07 से 08 अक्टूबर 2023 तक राजकीय अवकाश पर थीं एवं दिनाँक 09 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चिकित्सा अवकाश पर रही हैं। उसके बावजूद इज़ाज़त तामीर शाखा प्रभारी की जानकारी में लाये बिना प्रभारी का शाखा रजिस्टर प्रयोग में लाया गया जबकि इस शाखा में डिस्पैच का काम नहीं होता।
- महत्वपूर्ण बात कि यह डिस्पैच रजिस्टर इज़ाज़त तामीर शाखा में रखा जाता वह शाखा आयुक्त कार्यालय से लगभग दो-तीन किलोमीटर दूर है।
- आयुक्त कार्यालय में अपना स्वयं का डिस्पैच रजिस्टर है तो इज़ाज़त तामीर शाखा के डिस्पैच रजिस्टर का उपयोग क्यों और किस मंशा से किया गया?
- महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी आचार संहिता के बाद में बैक डेट पर पट्टे जारी किए जा रहे हैं।
- बैक डेट के अंदर अन्य शाखा द्वारा स्वयं को बचाते हुए पट्टे जारी कर रिश्वत लेकर पट्टे जारी किए जा रहे हैं जो की एक आपराधिक श्रेणी का भी घोतक है।
- सभी पट्टों जारी करने की रसीद भी 9 अक्टूबर 2023 की है जबकि गंगाशहर के 6 पट्टे ऐसे हैं जिनकी रसीद ऑफलाइन जारी की गई है।
- जारी किए गए पट्टों की रसीदें बैकडेट में काटी गई है।
- दलालों के द्वारा जिनका नाम तरुण खत्री व समुंदर सिंह है उनके माध्यम से मोटी रकम लेकर आयुक्त केसरलाल मीणा द्वारा यह पट्टे जारी किए गए।
- जिन दलालों तरुण खत्री और समुंदर सिंह के माध्यम भ्रष्टाचार हुआ है उनके ख़िलाफ़ पूर्व में नगर निगम सचिव बीकानेर द्वारा सरकारी पत्रावलियों में अनियमितता बरतने हेतु FIR भी दर्ज की गई है। यह FIR इन्हीं नगर निगम बीकानेर आयुक्त केसर लाल मीणा के निर्देशों पर करवाई गई थी किंतु अब केसर लाल मीणा इन्हीं दलालों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने लगे हैं।

सुनील और विजय दोनों सफाईकर्मी हैं। जो ड्राइवर का काम कर रहे हैं।

मैं सफाई कर्मचारी हूँ लेकिन बीकानेर नगर निगम ने मुझे आयुक्त सर का ड्राइवर लगा रखा है। 2018 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। फ़र्ज़ी पट्टा वितरण या कार्यालय के किसी भी काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सुबह 7 से दोपहर 2 की शिफ्ट का ड्राइवर हूँ। मेरा किसी भ्रष्टाचार से कोई सम्बंध नहीं!
-विजय ड्राइवर (सफाई कर्मचारी) नगर निगम बीकानेर

अजमेर रीजन के जलदाय विभाग का बड़ा घोटाला ED और ACB के आया संज्ञान में

जलदाय विभाग का मुँह काला कर रहे जलदाय के आला अधिकारी

जो खुल गया वह भ्रष्टाचार और जो दब गया उसका उद्धार

आचार संहिता के 3 दिन पहले विवादित फर्म मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन को दिया गया बड़ा टेंडर देगा 14 करोड़ का राजस्व नुक़सान

कार्यालय संवाददाता

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। जलदाय विभाग के पेयजल प्रोजेक्ट पर स्कीम में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार इस चरम पर है कि अजमेर क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम पहले 17% कम दर पर था और आचार संहिता से तीन दिन पहले केवल 1.03 कम दर पर दे दिया गया।

हालांकि शिक़ायत के बाद प्रवर्तन निदेशालय में सख़्ती के साथ गंभीरता से कार्यवाही हो रही है।एडिशनल चीफ इंजीनियर मुकेश गोयल व मैसेज यादव कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल व सीएमओ में एसीबी में भी परिवाद दर्ज हो चुका है।

परिवाद में अंकित है कि पेयजल सप्लाई के बहाने से टेंडर की दरों अनुसार 14 करोड रुपए का ज्यादा पेमेंट होगा जिसका सीधा-सीधा अर्थ भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है। अजमेर रीजन के पृथ्वीराज नगर में विजय राजे सिंधिया नगर में वाटर सप्लाई सिस्टम का काम जुलाई 2023 में मैसेज यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही बीएसआर से 17.21 लगभग कम दर यानी कि 3.50 करोड रुपए पर दिया गया था। पाइप लाइन जोड़ना व बिछाने का एक काम में मैसर्स प्रहलाद चौधरी ड्रिलिंग कंपनी को बीएसआर से 13.99 लगभग कम दर पर दिया गया।

अजमेर सिटी की प्रथम व द्वितीय डिवीजन में पेयजल सप्लाई के कार्यों के लिए 25.46 करोड़ का टेंडर जारी किया गया। इस कार्य के लिए दो कंपनी आई लेकिन एक कंपनी में मैसर्स राजाराम विश्नोई के दस्तावेज कम बताते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद में मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी को केवल 1.03 कम दर पर ही वर्कआर्डर दे दिया गया। टेंडर में सिंगल फॉर्म होने के बावजूद कोई दुबारा निविदा नहीं निकाली गई बल्कि एडिशनल चीफ इंजीनियर मुकेश गोयल ने मामले की जाँच तक नहीं की और नेगोशिएट भी नहीं किया जैसे वे यादव कंस्ट्रक्शन को सीधा रास्ता बनाकर दे रहे हों।ऐसे में इस कंपनी को विशेष तौर से फायदा पहुँचाने वाली सारी संदेह की सुइयाँ एडिशनल चीफ इंजीनियर मुकेश गोयल की ओर इशारा करती हैं। और साथ ही प्रमाणित करती हैं कि मैसर्स यादव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एडिशनल चीफ़ गोयल का विशेष याराना है।

कई बिंदु हैं जो जलदाय विभाग के इस बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं।

अब देखने वाली बात होगी कि ईडी, एसीबी जैसी जाँच एजेंसियाँ क्या खँगाल कर मामला बाहर लाती हैं।

हिलव्यू समाचार

सनसनीखेज़

विशेषांक

जयपुर, मंगलवार, 14 नवम्बर 2023

शातिर और क्रिमिनल माइंड का नाम है राजकुमार शर्मा पार्ट-2

राज्य के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक शिव गौतम भी FIR के लिए करना पड़ा संघर्ष

डॉ शिव गौतम व पत्नी राज्यश्री की बापूनगर SB 164 की हवेली पर राजकुमार शर्मा का नाज़ायज़ कब्ज़ा

डॉ शिव गौतम की पत्नी राज्यश्री दिवंगत आचार्य द्विजेश की बहन हैं जिनकी हवेली पर भी आचार्य के दिवंगत होते ही ट्रस्ट के नाम पर कब्जा कर लिया गया है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है सबसे बड़ी बात यह है कि हवेली आज भी डॉ शिव गौतम की पत्नी राज्यश्री के नाम है।

SB-164, बापू नगर हवेली जिसकी मालिक राज्यश्री गौतम हैं लेकिन राजकुमार शर्मा ने ट्रस्ट के नाम पर कब्जा कर लिया है।

12 अप्रैल 2023 को राज्यश्री गौतम और डॉ शिव गौतम ने अपने हक़ की आवाज़ उठाने के लिए आयोजित की प्रेस कॉन्फ्रेंस

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। मनोचिकित्सक शिव गौतम की पत्नी राज्य श्री गौतम ने मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं नवलगढ़ विधायक डॉ राजकुमार शर्मा पर प्लॉट नम्बर एस बी-164, गाँधी नगर मार्ग, बापू नगर पर कब्जा करने का आरोप लगाया और गाँधी नगर थाने में एफ आई आर दर्ज करवाई।

राज्यश्री ने 12 अप्रैल 2023 को प्रेस कोंफ्रेंस आयोजित कर मीडिया को बताया कि उनके बड़े भाई स्वर्गीय आचार्य द्विजेश शर्मा उनके यानी राज्यश्री के प्लॉट नम्बर एस बी-164 पर काफी लंबे समय से रह रहे थे। बीच-बीच में राज्य श्री अपने पति शिव गौतम के साथ अपने बड़े भाई द्विजेश शर्मा जी से मिलने भी जाती थीं और उनकी मृत्यु के पश्चात राज्य श्री गौतम अपने परिवार के साथ तीन दिन तक उपरोक्त प्लॉट पर रही और बाद में जब पुनः राज्य श्री उक्त प्लाट पर अंतिम संस्कार से सम्बंधित शेष कर्म-क्रियाओं को करने के लिए आई तो उन्हें परिवार के साथ राजकुमार शर्मा के लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि राजकुमार शर्मा ने अपने भाई राजपाल शर्मा, अपने साथी कमलकांत शर्मा उर्फ़ कमलचन्द्र एवं उमेश शर्मा के साथ मिलकर उक्त प्लाट पर कब्ज़ा कर लिया था साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों में शोकाकुल सन्देश में परिजन के रूप में केवल स्वयं के व अपने पुत्र के नाम को अंकित किया। और स्वयं को आचार्य द्विजेश जी का निकटम रिश्तेदार बताने का झूठा प्रयास किया।

प्रेसवार्ता के दौरान SB-164 बापू नगर की रजिस्ट्री दिखाते हुए गौतम दम्पत्ति

राज्यश्री ने उपरोक्त प्लॉट के सम्बंधित स्वयम के मालिकाना हक़ के कागज़, बिजली, पानी, यूडी टेक्स के बिल और व अन्य साक्ष्य मीडिया के सम्मुख प्रस्तुत किये और राजकुमार शर्मा एवं उसके साथियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही करने की बात रखी। उसके पश्चात उन्होंने न्यायालय में अपना परिवाद देकर गाँधी नगर थाने में FIR करवाई और मुक़दमा दर्ज किया जो अभी न्यायालय में चल रहा है।

आचार्य द्विजेश की जमवारामगढ़ की करोड़ों की ज़मीनों पर फ़र्ज़ी शपथ पत्रों व फ़र्ज़ी हस्ताक्षर द्वारा कब्जा

आचार्य की जमवारामगढ़ की ज़मीनें जिन पर राजकुमार शर्मा द्वारा कब्जा किया गया है।

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर। ग्राम मेदराजसिंहपुरा तहसील जमवारामगढ़ और ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर की जमीनें भू राजस्व रिकॉर्ड में आचार्य द्विजेश और उनके भाई हरि शर्मा के संयुक्त नाम से थी। हरि का देहांत 28.01.2017 को हो गया। हरि भी अविवाहित नाऔलाद था। निधन के बाद हरि का हिस्सा पहले तो आचार्य द्विजेश के नाम फिर राजकुमार शर्मा ने अपने नाम नामांतरण करवाया फिर युवराज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी (गोनेर वाली जमीन, कम्पनी में विधायक राजकुमार निदेशक है) और विधाकल्याण ट्रस्ट (मेदराजसिंहपुरा की जमीन) के नाम नामांतरण करवाया। इस प्रकार राजकुमार ने स्वर्गीय आचार्य हरि शर्मा का एकमात्र वारिस आचार्य द्विजेश को बताया है।

सांगानेर तहसीलदार को आचार्य द्विजेश द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में गवाह न्याय व्रत शर्मा पुत्र स्वर्गीय आचार्य कल्याण शर्मा अंकित है लेकिन न्याय व्रत शर्मा के हस्ताक्षर नहीं हैं।शपथ पत्र भी फ़र्ज़ी है। न्याय व्रत शर्मा का पिता द्वारका बताया गया है लेकिन तहसीलदार सांगानेर को आचार्य द्विजेश द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में गवाह के रूप में न्याय व्रत शर्मा का पिता स्वर्गीय आचार्य कल्याण अंकित है।

आचार्य द्विजेश की गोनेर और मेदराजसिंहपुरा में जमीन को हड़पने के लिए राजकुमार शर्मा ने वैध कागजों के रूप में प्रयोग करने के लिए अवैध कागजों की कूट रचना, फर्जी हस्ताक्षर, धोखाधड़ी, षड्यंत्र किया है।

युवराज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक और विधाकल्याण ट्रस्ट के कागजों में राजकुमार शर्मा का नाम अंकित है। अगर गहनता से जाँच ऐजेंसी द्वारा इस षड्यंत्र और धोखाधड़ी की जाँच की जाए तो माफ़ियामेन राजकुमार शर्मा के काले कारनामे बेहद सरलता से उजागर हो सकते हैं क्योंकि हर दस्तावेज़ों में फर्जीवाड़ा और झूठ आसानी से पकड़ा जा सकता है।

राजकुमार शर्मा द्वारा बनाई गयी सभी कम्पनियों व संपत्तियों की गहनता से हो जाँच

- राजकुमार शर्मा की पत्नी परमजीत कौर, पुत्र युवराज व अन्य परिवार सदस्यों के नाम से बनी कंपनियों की जाँच से कई ख़ुलासे होंगे।
- कंपनी बनाने के कई मामले आज भी जाँच के दायरे में हैं। नवलगढ़ क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री किसकी है,क्यों है, कैसे है?
- सीमेंट फैक्ट्री के सारे काम व पावर P S INFRA के नाम से कंपनी बनाकर रामकुमार शर्मा ने 2020 में खुद ने ले लिए।
- इस फैक्ट्री से नवलगढ़ क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ इसके 95 % कर्मचारी बाहर से लाये गए हैं।
- परमराज कौर राजकुमार शर्मा की तलाक शुदा पत्नी है जो आज भी इसके साथ रहती है और सारे काले सफेद बिजनेस साथ सम्भालती है और सुलोचना शर्मा जो इसके सहायक उमेश शर्मा की पत्नी है। PS इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन दोनों महिलाओं के नाम से ही है। सीमेंट फैक्ट्री से करोड़ों रुपये का लाभ लिया है राजकुमार शर्मा ने लेकिन विकास किसका हुआ है यह देखने वाली बात है।

मुहाना मंडी के सामने 100बीघा पर भी राजकुमार शर्मा का था कब्ज़ा लेकिन जेडीए ने कब्ज़ा छुड़वाया

04 वर्ष पहले जयपुर मुहाना मंडी के सामने 100 बीघा सरकारी जमीन पर राजकुमार शर्मा ने अपने माफ़िया गुट के साथ मिलकर कब्जा कर लिया था और यहाँ तक कि प्लॉट काटकर बेच भी दिए थे लेकिन समय रहते जागरूक और ईमानदार तात्कालीन कलेक्टर एवं तात्कालिन जेडीए मुख्य प्रवर्तन अधिकारी ने कब्जा छुड़वा लिया। इसका रिकॉर्ड जेडीए में आज भी सुरक्षित है।

नवलगढ़ में भी कई सरकारी ज़मीनों, नालों और फॉर्म हाउस पर है कब्ज़ा

नवलगढ़ के बदराना में जहाँ पशु मेला आयोजित होता था उसकी 200 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया तथा प्लॉट काट कर बेचने की कोशिश की। मामला अभी भी न्यायालय लंबित है। कई सरकारी ज़मीनों,पुरानी हवेलियों, नालों,फार्मों पर कब्जा करके राजकुमार शर्मा लगातार दूसरों की निजी सम्पत्तियों,सरकारी ज़मीनों और जनता के हक़ पर आधिपत्य जमाता आ रहा है।

नवलगढ़ के स्थानीय जनता की हिन्दू धार्मिक आस्था को राजकुमार शर्मा पहुँचाई चोट

नवलगढ़ मंडी गेट स्थित गोयनका (चौधरी की बगीची) व शमशान में स्थित सैकड़ो वर्ष पुराने शिव मंदिर,हनुमान मंदिर और भैरव मंदिर को तोड़ा गया और उसके इर्द गिर्द की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोगों की आस्था बहुत धार्मिक अवस्था को भी ठेस पहुंची है। राजकुमार शर्मा द्वारा भूमाफ़ियायों के माध्यम से कब्जा करवाने का प्रयास किया गया।

गोनेर के जंगलों की करोड़ों की ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया है राजकुमार शर्मा ने

धन और बल से जेडीए की जाँच कमेटियों को भी किया अपने वश में

जेडीए में राजकुमार शर्मा की गाड़ी खड़ी रहती है निरंतर

शालिनी श्रीवास्तव

जयपुर (हिलव्यू समाचार)। जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का.. ऊक्त मुहावरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और नवलगढ़ विधायक रहे राजकुमार शर्मा पर पूरी तरह से चरितार्थ हुआ है क्योंकि निजी व सरकारी जमीनों पर जबरन और गुंडागर्दी के साथ कब्जा करना इनकी पहचान है।

सरकारी नियम,क़ानून, क़ायदों को ताक पर रखकर सरकारी व निजी ज़मीन पर कब्ज़ा करना उन पर अवैध निर्माण करवाना राजस्थान के इस फ़र्ज़ी राजकुमार की आदत में आ गया है। बेख़ौफ़ मुख्यमंत्री सलाहकार राजकुमार शर्मा तमाम सरकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए जयपुर कॉलेज के संस्थापक मृतक आचार्य द्विजेश शर्मा की ग्राम गोनेर हल्का गोनेर तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 3383 लगभग 30 बीघा ज़मीन पर कब्ज़ा तो कर ही बैठे साथ-साथ उसके आसपास की सरकारी व जंगलात की 570 बीघा ज़मीन पर भी कब्ज़ा करने को उतारू हो गए हैं। वन विभाग के हरे भरे पेड़ों की कटाई करवा चुके हैं।

गोनेर गाँव के लगभग 570 बीघा जंगलात (ग्रास फार्म) की जमीन पर अनगिनत पेड़ काटे गए और ग्राम गोनेर में जंगलात की सरकारी ज़मीन के चारों ओर 8-10 फीट ऊंची दीवार सरकारी खर्च से बनाई गयी ताकि बाहर से कोई देख न सके और बचे हुए लाखों पेड़ों को काटा जा सके। पेड़ काटने और अवैध कब्ज़ा करने पर जब विरोध दर्ज हुआ तो कहा गया कि इन पेड़ों की जगह फलदार, छायादार पेड़ लगाए जाएंगे।सरकार के किस विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति दी? किसने पेड़ काटे? कटे हुएपेड़ कहां गए? उनकी कीमत किसने ली? यह कोई नहीं जानता। आम आदमी अब उस जमीन में प्रवेश नहीं कर सकता आम रास्ता बंद कर दिया गया है। जंगलात की जमीन गोनेर गाँव ष्की है।

आचार्य द्विजेश की 30 बीघा जमीन पर बनाया अवैध होटल। जिसकी आड़ में जंगलात की 570 बीघा जमीन पर किया कब्ज़ा।

जेडीए की टीम ने स्वयं ने देखे थे अवैध होटल की आड़ में गोनेर के कटे हुए हरे-भरे पेड़

हज़ारों कटे हुए पेड़ों के ठूँठ

जेडीए की कार्यवाही ठंडे बस्ते में क्यों?

- एक सोशल एक्टिविस्ट ने जब 6 जून 2023 को जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, सचिव, एवं निदेशक विधि को लिखित शिकायत दर्ज की तो कुम्भकर्णी नींद सोया जेडीए जागा और उसके बाद तीन-तीन लोगों दो अलग-अलग कमेटी बना कर दोनों मौकों पर जाकर जाँच कर रिपोर्ट करने के आदेश जारी किये।
- गोनेर कमेटी में मनीष कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी, धर्मराज गुर्जर पटवारी, प्रमोद सिंह शेखवात स्थायी अधिवक्ता जेडीए अधिकरण,एवं जमवारामगढ़ कमेटी में विजय दायमा कनिष्ठ विधि अधिकारी, धर्मराज गुर्जर पटवारी,मनमोहन अरोड़ा स्थायी अधिवक्ता जेडीए,अधिकरण को नियुक्त कर आदेश दिये गए।
- दिनाँक 19 जून 2023 को जेडीए विधि निदेशक द्वारा गठित जाँच कमेटी मौक़ा स्थल पर गोनेर ग्रास फार्म पर पहुँची जिसे हिलव्यू समाचार ने भी लगातार कवरेज़ किया।
- जेडीए विधि निदेशक दिनेश गुप्ता द्वारा गठित टीम ने भी हरे-भरे पेड़ों के कटे हुए सर देखे।
- निराशा व राजकुमार शर्मा के अन्याय में डूबे कटे हरे-भरे पेड़ अपनी दुर्दशा की कहानी ख़ुद कह रहे थे।आसपास के ग्राम वासियों ने भी पुष्टि की कि यहाँ जंगलात से गुज़रने के दो कच्चे रास्ते थे वह भी राजकुमार शर्मा के गुंडों और भूमाफ़ियाओं ने कब्जा कर बन्द कर दिए हैं अब इधर ग्रामवासियों का आना भी लगभग बन्द हो गया है। गोनेर जाँच कमेटी ने हिलव्यू समाचार की टीम के समक्ष भी माना कि पेड़ों की अवैध कटाई करके जेडीए व जंगलात की ज़मीन पर कब्जा किया गया है।
- कमेटी ने रिपोर्ट में भूमि सीमांकन,पेड़ों की कटाई व वन विभाग से अन्य जानकारी के लिए कुछ बिंदु अंकित किये।

हालाँकि उस दौरान भी जाँच कमेटी की टीम ने जेडीए की सरकारी ज़मीन पर बन रहे अवैध होटल निर्माण पर ध्यान नहीं दिया न ही अवैध निर्माण को भीतर से जाकर मौक़ा मुआयना किया केवल पुनः सीमांकन की बात रिपोर्ट में अंकित की गई है।

मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी हैं पार्टनर

इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की भी पार्टनरशिप है जिनकी शैय पर राजकुमार शर्मा एक पागल निरंकुश हाथी की तरह चारों तरफ जंगलों को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत के पुत्र वैभव की 50% हिस्सेदारी,यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 25% हिस्सेदारी और 25% स्वयं की हिस्सेदारी लेकर राजकुमार शर्मा द्वारा पूरी गुंडागर्दी के साथ लगातार जंगलात व जेडीए की ज़मीनों पर कब्जे जारी हैं।

आचार्य द्विजेश की गोनेर संपत्ति पर राजकुमार शर्मा ने कैसे किया कब्ज़ा

वर्ष 1991 में आचार्य द्विजेश की गोनेर की यह जमीन असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के आदेश के द्वारा श्री उम्मेद सिंह के नाम चढ़ाई गई। सेटलमेंट डिपार्टमेंट को केवल चकबंदी करने, नक्शा बनाने का अधिकार है, मालिकाना हक तय करने का अधिकार राजस्व विभाग के अधिकारियों यथा पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, आर.ए.ए., संभागीय आयुक्त, राजस्व मंडल और राजस्व मंत्री को अधिकार है। लंबे समय तक कब्जा होने पर कब्जाधारी द्वारा दावा करने, सुनवाई के बाद राजस्व अधिकारी द्वारा 10 बीघा जमीन ही 25 परसेंट डीएलसी रेट पर आवंटित करने का अधिकार है। उम्मेद सिंह को आवंटन ही गलत हुआ था।उम्मेद सिंह की मृत्यु के बाद वर्ष 2019 में विरासत का नामांतरण खोला गया है, उसके बाद वर्ष 2022 में बेचान का नामांतरण युवराज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम खोला गया है।

तथाकथित रूप से वसीयत, गोदनामा, गिफ्टनामा विधायक राजकुमार शर्मा के 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र युवराज शर्मा के नाम किए जाने की बात सामने आई लेकिन यदि नामांतरण खुला तो नाबालिग युवराज के नाम खुलता फिर डायरेक्ट नाबालिक युवराज ने युवराज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इस संपत्ति को कब बेचा?गिफ्ट दिया?कैसे ट्रांसफर किया?उसकी रजिस्ट्री करवाई या नहीं करवाई? स्टांप शुल्क जमा करवाया या नहीं करवाया? इन सभी तथ्यों, वैध प्रमाणों के आधार पर ही जेडीए पट्टा जारी कर सकता है। जेडीए पट्टा जारी होने के बाद स्टांप शुल्क जमा करवा कर पंजीयन करवाना आवश्यक है, जेडीए नक्शा पास करवाने के बाद ही निर्माण किया जा सकता है लेकिन खालमेल और फ़र्ज़ीवाड़ा करके कब्जा कर लिया गया है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, एवं मुद्रक शालिनी श्रीवास्तव के लिए अम्बर ऑफसेट प्राइवेट लिमिटेड, डी.एल. टॉवर, 3-ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र, जेएलएन मार्ग, जयपुर में मुद्रित एवं प्लॉट नंबर C-2,अर्शिया रेजिडेंसी, फ्लैट नंबर 201,आदर्श नगर,राजा पार्क जयपुर-302004 (राजस्थान) से प्रकाशित।

संपादक : शालिनी श्रीवास्तव **सह-संपादक:** हरीश श्रीवास्तव, छबड़ा बारां **सह-संपादक :** कुलदीप गुप्ता, जयपुर मो.: 9460678701, 7976561127 (21 जून 2014 से निरन्तर प्रकाशित) hillviewsamachar@gmail.com (राजस्थान सरकार से विज्ञापन हेतु स्वीकृत)